मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

सांध्य दैनिक

रांची, मंगलवार, 18 अगस्त 2026

संवत 2083, श्रावण शुक्ल 6 मूल्य-3 रुपये

वर्ष-9, अंक 335, पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ▸▸ आरोप लगा, नौकरी गई, क्या जांच हुई?

इमरान हाशमी ने ली आवारापन से 10 गुना ज्यादा फीस ◂◂ 6

झारखंड में आज भारी बारिश

रांची समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश व वज्रपात का यलो अलर्ट

- लगातार बारिश से पंचेत और चांडिल डैम के खुले फाटक,गेतलसूत डैम का पानी खतरे के निशान के करीब
- बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दवाब के कारण सक्रिय हुआ मानसून

संवाददाता

रांची : राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में सोमवार देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा।

चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में रेड अलर्टः आईएमडी के अनुसार, कुछ जगहों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं, एक-दो स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू और लातेहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि रांची समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा : मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कई जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

19 से 23 अगस्त तक भी बारिशः 19 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 20 और 21 अगस्त को बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन गरज और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। 22 अगस्त को कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है। 23 अगस्त को कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

बारिश से कई जिलों में मौसम सुहावनाः बारिश और बादलों के कारण रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रह सकता है। हालांकि, बारिश और बिजली चमकने के दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतनी चाहिए।

जेजेएमपी के सब-जोनल कमांडर समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार, एके 56 और एसएलआर बरामद

संवाददाता

रांचीः गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को उग्रवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी (झारखंड जन मुक्ति परिषद) के सब-जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रामदेव लोहरा पर पुलिस की ओर से पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था।

गुप्त सूचना पर कारवाईः आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि खखटढ का सब-जोनल कमांडर रामदेव लोहरा डुमरी थाना क्षेत्र के अकासी और जयरागी गांवों के आसपास अपने दस्ते के सदस्यों के साथ घूम रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद गुमला एसपी के नेतृव में सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके में अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान टीम ने घेराबंदी कर रामदेव लोहरा समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

पांच लाख का इनामी है लोहराः गिरफ्तार आरोपियों में रामदेव लोहरा, पिता बालमुकुंद लोहरा, ग्राम बिंगड़ा, थाना लातेहार, जिला लातेहार शामिल है। पुलिस के मुताबिक रामदेव लोहरा खखटढ का सब-जोनल कमांडर है और उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। दूसरा गिरफ्तार आरोपी अरविंद नायक, पिता सहदेव नायक, ग्राम कोने, थाना लातेहार, जिला लातेहार है, जो जेजेएमपी का एरिया कमांडर बताया गया है।

इसके अलावा मुनेश्वर सिंह, पिता सोहराय सिंह, ग्राम किता मक्का, थाना जोबांग, जिला लोहरदगा को खखटढ का सदस्य बताया गया है। चौथे गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र लोहरा, ग्राम उजरा, थाना डुमरी, जिला गुमला के रूप में हुई है।

हथियार और अन्य सामान बरामद : गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोलियां और अन्य सामान बरामद किए हैं। बरामदगी में एक अङ-56 राइफल और मैगजीन, एक रछफराइफल और मैगजीन तथा एक सेमी-ऑटोमेटिक राइफल शामिल है। इसके अलावा एके 47, एसएलआर और सेमी-ऑटोमेटिक राइफल के लिए इस्तेमाल होने वाले जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अभियान के दौरान एक वॉकी-टॉकी, आठ मोबाइल फोन, एक वाई-फाई डोंगल और प्रतिबंधित जेजेएमपी /नक्सली संगठनों से संबंधित पर्चे भी जब्त किए हैं।

भिंड-ग्वालियर हाईवे पर पिकअप-डंपर की टक्कर, 8 मजदूरों की मौत, 25 घायल

भिंड : मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे-719 पर सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया। गोहद के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में पिकअप सवार आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।

हादसा रात करीब एक बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में चालक ने पिकअप को मोड़ दिया। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि

पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गोहद चौराहा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त पिकअप से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के अनुसार, हादसे में आठ मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हैं। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस मृतकों और घायलों की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम करने आए थे। काम पूरा होने के बाद वे पिकअप से अपने गांव लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश लौट रहे थे। रात के सफर के दौरान छीमका गांव के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया।

मवेशियों को बचाने के दौरान हुआ हादसाः पुलिस की शुरूआती जांच में सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने की कोशिश को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक मवेशी आने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, पुलिस हादसे की अन्य परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। हादसे के बाद कुछ समय तक एनएच-719 पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल

विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी नियुक्त,सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी

नई दिल्ली : बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के चुनावों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है।

पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई

है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे में चुनाव की कमान तावड़े को सौंपे जाने को अहम माना जा रहा है।

पंजाब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया को दी गई है। पंजाब में बीजेपी के सामने संगठन को मजबूत करने और अपने चुनावी आधार का विस्तार करने की चुनौती है। वहीं, राज्यसभा सांसद तरुण चुग को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुग पहले भी पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं, पूर्व आरएसएस नेता राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पार्टी ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष को उनके पद पर बरकरार रखा है। मीडिया की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास ही रहेगी, जबकि सोशल मीडिया की कमान छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को सौंपी गई है। बीजेपी के इस संगठनात्मक फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनावों पर पार्टी का खास फोकस साफ नजर आ रहा है। यूपी, पंजाब और गुजरात में अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को और धार देने का संकेत दिया है।

मौत की सजा में फांसी ही जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार चाहे तो तलाश सकती है दूसरा तरीका

फांसी की जगह जहरीले इंजेक्शन की मांग वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली(एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मौत की सजा पाए कैदी को फांसी देने के मौजूदा तरीके को खत्म कर उसकी जगह नसों में जहरीला इंजेक्शन देने, को अपनाने की मांग की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि उनके फैसले से केंद्र सरकार को फांसी देने के मौजूदा तरीके की किसी एक्सपर्ट कमेटी के जरिए व्यापक समीक्षा करने से नहीं रोका जाएगा। इस समीक्षा का मकसद यह देखना होगा कि क्या फांसी देने का कोई दूसरा तरीका, सजा पाए कैदी की गरिमा बनाए रखते हुए और अनावश्यक दर्द को कम करते हुए, संवैधानिक मकसद को बेहतर ढंग से पूरा करता है।

बेंच ने यह फैसला सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा की 2017 में दायर याचिका पर सुनाया। इस याचिका में कानून से मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी देने के मौजूदा तरीके को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में मौत की सजा पाए कैदी को फांसी देने के तरीके को खत्म करने और उसकी जगह कम दर्दनाक तरीकों, जैसे नसों में जहरीला इंजेक्शन, गोली मारना, बिजली का झटका देना या गैस चैंबर का इस्तेमाल करने की मांग की गई थी।

बहस के दौरान, मल्होत्रा ने कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को कम से कम यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह फांसी या जहरीले इंजेक्शन में से किस तरीके से सजा पाना चाहता है। मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात की जांच के लिए एक्सपट्र्स की एक कमेटी बनाने पर विचार कर सकता है कि क्या फांसी देकर मौत की सजा देना सही और कम दर्दनाक है। साथ ही, कोर्ट ने केंद्र से सजा देने के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर बेहतर डेटा भी मांगा था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वह विधायिका को सजा पाए कैदियों को सजा देने का कोई खास तरीका अपनाने का निर्देश नहीं दे सकता। 2018 में, केंद्र ने उस कानूनी प्रावधान का पुरजोर समर्थन किया था जिसके तहत मौत की सजा पाए कैदी को केवल फांसी ही दी जा सकती है। केंद्र ने बेंच को बताया था कि सजा देने के दूसरे तरीके, जैसे जहरीले इंजेक्शन और गोली मारना, कम दर्दनाक नहीं हैं।

गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि फांसी से मौत तेज, आसान होती है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती जो कैदी की तकलीफ को बेवजह बढ़ाए।

यह हलफनामा उस पीआईएल के जवाब में दायर किया गया था,

चुनाव में गलत हथकंडे अपनाने वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक

सत्ता बदलते ही केस वापस लेने के खेल पर लगी रोक

नई दिल्ली (एजेंसी) : भारतीय चुनावी राजनीति में काले धन और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा फैसला सुनाया है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी या काले धन के इस्तेमाल के आरोपी नेताओं पर सरकार बदलते ही राजनीतिक रसूख के चलते दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। इस मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सांसदों-विधायकों की तरह उम्मीदवारों पर भी लागू होगा नियम

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के। सिंह की पीठ ने मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े पुराने नियम का हवाला देते हुए यह बड़ा आदेश दिया। पीठ ने कहा कि जिस तरह मौजूदा सांसदों और विधायकों के मुकदमे केवल हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वापस हो सकते हैं, ठीक वही नियम अब चुनाव लड़ने वाले सामान्य उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे संभावित उम्मीदवारों को कड़ा संदेश जाएगा कि गलत काम करके कोई भी नेता सिर्फ सत्ता परिवर्तन के दम पर बच नहीं सकता।

राजनीतिक लाभ के लिए केस वापस लेना न्याय प्रणाली के खिलाफः अदालत ने राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद मुकदमों को वापस लेने की परिपाटी पर गंभीर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राजनीतिक बदलाव के बाद अक्सर ऐसे अनुचित फैसले लिए जाते हैं, जो निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल भावना के पूरी तरह खिलाफ हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों से नैतिक ईमानदारी और निष्पक्षता की पूरी उम्मीद रखता है। लोकतंत्र, कानून का शासन और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और इनमें से किसी से भी समझौता व्यवस्था को कमजोर करता है।

10 लाख से ज्यादा कैश मिलने पर इनकम टैक्स का शिकंजा, 1 साल में जांच पूरी करने का निर्देश : काले धन के बेलगाम इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव के दौरान चेकिंग में यदि स्टैटिक सर्विलांस टीम को 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी मिलती है, तो तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सक्रिय कर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही, अदालत ने जांच अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केस दर्ज होने की तारीख से एक साल के भीतर जांच हर हाल में पूरी की जाए, ताकि चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को समय पर सजा दिलाई जा सके।

आंदोलन का 25वां दिन

सरकार के फैसले पर छात्रों का जश्न, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े, बोले- आधी जीत हुई

संवाददाता

रांची: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 25वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से छात्रों की लगभग सभी प्रमुख मांगों को मान लिए जाने के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्रों ने जश्न मनाया और कुछ आंदोलनकारियों ने अपना अनशन भी समाप्त कर दिया। हालांकि, आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अपने फैसलों को लिखित रूप में नहीं देती और जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती, तब तक आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा।

टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने के फैसले से खुशीः सरकार की ओर से टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं और उससे जुड़ी भर्तियों को रद्द करने की घोषणा के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे अपनी मांगों की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों ने खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। इसी बीच कुछ छात्रों ने अपना अनशन भी समाप्त कर दिया। हालांकि, छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन की अंतिम जीत नहीं है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से लिए गए फैसलों को लिखित रूप में जारी किया जाना जरूरी है।

सीबीआई जांच की मांग पर अब भी दो छात्र भूख हड़ताल परः जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रूपेश कुमार और सबीता कुमारी अब भी भूख हड़ताल पर हैं। दोनों आंदोलन स्थल पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उइक जांच की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए जब तक इस मांग पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग मानी गईः मयंक राजपूत : छात्र नेता मयंक राजपूत ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांगों में सीजीएल परीक्षा को रद्द करना भी शामिल था, जिसे सरकार ने मान लिया है। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। हालांकि, मयंक राजपूत ने कहा कि सरकार ने जिन मांगों को स्वीकार किया है, उन्हें लिखित रूप में देना जरूरी है। इसके साथ ही जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच भी आवश्यक है।

सीबीआई जांच से बड़े लोगों तक पहुंच सकती है जांचः मयंक राजपूत ने कहा कि सीबीआई जांच होने से मामले में शामिल बड़े लोगों तक जांच पहुंच सकती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की यह आधी जीत है और इसे पूरी जीत तब माना जाएगा, जब सरकार जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी। उनका कहना है कि छात्रों का उद्देश्य सिर्फ परीक्षाओं को रद्द कराना नहीं, बल्कि कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंचाना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराना भी है।

सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलनः छात्र नेता कुणाल कुमार ने भी स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि सरकार के फैसलों के बाद आंदोलन को लेकर सकारात्मक माहौल जरूर बना है, लेकिन उनकी अंतिम और महत्वपूर्ण मांग अभी बाकी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान

जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए हुई सभी सभी परीक्षाएं और परिणाम रद्द

रांचीः झारखंड में जेपीएससी- जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी रहा। इस बीच छात्रों और सरकार के बीच प्रस्तावित वार्ता होते-होते नहीं हो सकी। हालांकि इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा एलान कर दिया है। सीएम सोरेन ने टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, टीडीपीएल द्वारा जारी किए गए परिणाम तथा टीडीपीएल के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार का चयन या भागीदारी रद्द करने की बात कही है।

सीएम सोरेन ने क्या कहा? : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमने इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए विशेष कैबिनेट बैठक की। सभी पहलुओं पर विचार करने और समस्याओं का समाधान तलाशने के बाद हमने फैसला लिया है कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, टीडीपीएल द्वारा जारी किए गए परिणाम तथा टीडीपीएल के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार का चयन या भागीदारी रद्द की जाती है। इस संबंध में टीडीपीएल द्वारा की गई सभी गतिविधियां भी रद्द कर दी गई हैं।

राहुल गांधी की चिट्ठी से बढ़ा राजनीतिक दबावः जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी।

5 लाख के 985 ग्राम अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

संवाददाता

चतराः जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को चतरा पुलिस ने सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी कार्रवाई में 5 लाख रु मूल्य के 985 ग्राम मादक पदार्थ अफीम के साथ मोटरसाइकिल सवार दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय में आज आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहब ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति लावालौंग थाना क्षेत्र से अफीम की खेप लाकर पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की बिक्री करने जाने वाले हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लावालौंग- बगरा रोड में मोटरसाईकिल से आ रहे दो व्यक्ति को अवैध अफीम के साथ पकड़ा गया। बताया कि बरामद अफीम का अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रु है। गिरफ्तार तस्करो में लावालौंग थाना क्षेत्र के टुनगुन गांव निवासी सुधीर ठाकुर (32 वर्ष) पिता- नान्हू ठाकुर एवं खनगड्डा गांव के सुरेश गंझू (35 वर्ष) पिता-स्वः सोमर गंझू का नाम शामिल है।इस संदर्भ में सिमरिया थाना काण्ड संख्या 145/26, दिनांक-17.08.2026, धारा - 08/17(बी)/18(सी)/28/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।छापामारी दल में सिमरिया के अंचलाधिकारी,सिमरिया थाना प्रभारी पुअनि अमित कुमार गुप्ता,आ0/292 संजीव कुमार,आ0/273 शंकर प्रसाद मेहता एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गांव पहुंचा टीएसपीसी का एरिया कमांडर मोछू गिरफ्तार

2024 में दो पुलिसकर्मियों की हत्याकांड में शामिल था नक्सली

संवाददाता

चतराः जिले की पुलिस ने एसपी अनिमेष नैथानी को मिली गुप्त सूचना पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सक्रिय एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोछु उर्फ लखन गंझू (40 वर्ष) को लावालौंग थाना क्षेत्र के परामातु गाँव से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वह अपने गांव परामातु में आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हुआ था। आज आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि पुलिस को 16 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोछु उर्फ लखन गंझू श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव परामातु आने वाला है। सूचना के आधार पर सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नागरगोजे शुभम भाऊसाहेब के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण गंझू को उसके घर परामातु से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादी लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी ने बताया कि लक्ष्मण गंझू टीएसपीसी संगठन में काफी सक्रिय था। वर्ष 2024 में सदर थाना क्षेत्र में अफीम विनष्टीकरण अभियान से लौट रहे पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर किए गए हमले की साजिश में वह शामिल था। इस घटना में दो पुलिस जवान शहीद हुए थे। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ वशिष्ठनगर थाना और सदर थाना में कुल तीन मामले दर्ज हैं।

तीन लाख मूल्य का 15 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद

संवाददाता

चतराः चतरा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई एक कार्रवाई में 15 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर प्रिंस कुमार(20 वर्ष) पहरा गांव का रहनेवाला है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिमरिया के एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊसाहब ने बताया कि चतरा एसपी अनिमेष नैथानी को तड़के गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम-सलीमपुर मैदान के पास दो व्यक्ति अवैध रुप से ब्राउन शुगर की खरीद ब्रिकी करने के लिए आने वाले हैं। सूचना के बाद उनके नेतृत्व में गठित छापामारी दल ने त्वरित कारवाई करते हुए अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। वहीं एक अन्य एक व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि बरामद ब्राउन सुगर की अनुमानित मूल्य लगभग तीन लाख रु है। इस संदर्भ में गिद्धौर थाना कांड सं0- 84/26, दिनांक 17.08.2026, धारा-17 (बी0)/21 (बी०) /22 (बी0)/27 (ए०)/28/29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में चोरी का खुलासा, दो गिरफ्तार

संवाददाता

चतराः जिले के ईटखोरी थाना क्षेत्र के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परोका गांव निवासी तुषार कुमार तथा इटखोरी निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर विद्यालय से चोरी किये गए कई सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी में प्रयुक्त बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। उन्होंने बताया कि विगत 15 अगस्त की रात परियोजना बालिका उच्च विद्यालय ईटखोरी के एक कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने

लोहे का एक अलवीरा, एक बड़ा बैटरी, एक इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरा, एक मॉनिटर, दो कीपैड मोबाइल, दो स्मार्टफोन की चोरी कर ली थी। घटना को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक बिनीत कुमार ने थाना में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन के आधार पर ईटखोरी थाना मे प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि विद्यालय से चोरी किए गए सामान के साथ अपराधकर्मी एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर परोका की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही ईटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने परोका में घेराबंदी कर बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल पर चोरी का सामान लदा हुआ था।पुलिस ने मौके से दो युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों की निशानदेही पर चोरी के अन्य सामान को झाड़ी में छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने झाड़ी में छापेमारी कर वहां छिपाकर रखे गए अन्य सामान को भी बरामद कर लिया। छापेमारी दल में ईटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह, एएसआई बिदेश कुमार पाण्डेय, पंकज कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

जलजमाव और गंदगी से मलेरिया समेत कई बीमारियों का मंडराया खतरा

चतराः लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं अब यह परेशानी का सबब भी बनने लगी है। बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव और गंदगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू सहित अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई स्थानों पर नालियां जाम हैं और बारिश होने पर नालियों का गंदा पानी सड़क पर आ जा रहा है। यही जमा पानी मच्छरों के पनपने का प्रमुख कारण बन रहा है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है, जिससे लोगों में बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में नियमित रूप से साफ-सफाई और जलजमाव वाले स्थानों पर दवा का छिड़काव जरूरी है। लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से तत्काल सफाई अभियान चलाने तथा मच्छररोधी दवा का छिड़काव कराने की मांग की है।

जेएसएससी सीजीएल रद्द होते ही मचा बवाल

नौकरी पा चुके अभ्यर्थी धरना पर, बोले- हमारा क्या दोष?

प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद, सड़क पर उतरे कर्मचारी

संवाददाता

रांची: झारखंड सरकार की ओर से सोमवार को जेएसएससी सीजीएल

परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। परीक्षा के जरिए नियुक्त होकर अपने-अपने पदों पर सेवा दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और न्याय की मांग कर रहे हैं।

परीक्षा रद्द होने से नियुक्त अभ्यर्थियों में नाराजगीः झारखंड सरकार के सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (जेएसएससी सीजीएल) रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के एक वर्ग में नाराजगी सामने आई है। उनका कहना है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की और नियुक्ति के बाद अपने पदों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना शामिल था।

'हमने निष्पक्ष प्रक्रिया से परीक्षा पास की, फिर हमारा क्या दोष?' : प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने अठक से कहा, हमने निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए परीक्षा पास की और नियुक्त हुए हैं, फिर हमारे साथ ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? हम तो कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे थे। अगर जांच में कोई गलती सामने आती है, तो उसमें शामिल संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, सरकार के इस फैसले के बाद मैं फिर सड़क पर आ गया हूं। मैं अपने माता-पिता से कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें। हम दोबारा जीतेंगे। सरकार से भी अपील है कि अपने इस फैसले को वापस ले। प्रदर्शनकारी ने आगे कहा कि सरकार का यह फैसला उसके अनुसार अदालत के आदेश की भी अवहेलना करता है। उसने कहा कि आज न्याय की हार हुई है और वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के निर्णय की विस्तृत रिपोर्ट

संवाददाता

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आजीवन कारावास भुगत रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई से जुड़े कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने सरकार से राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की 30 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए निर्णय पर विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

इससे पहले सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक निर्धारित 3 माह में देरी का कारण स्पष्ट किया गया। लेकिन वर्तमान में हुए राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी।

झालसा की ओर से अधिवक्ता सुभम मिश्रा ने पक्ष रखा। वहीं हाईकोर्ट की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा। यहां बता दें कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक समय से करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश दिया है। हर तीन माह में स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की बैठक होनी है। इसी आदेश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट जनहित याचिका के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है।

हाईकोर्ट ने सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार सिविल कोर्ट में 10 अक्टूबर 2022 को हुई हिंसक घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों को लातेहार के समान व्यक्तिगत सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सीधे तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इससे संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाया। साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया।

वर्ष 2022 में लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में हुई थी हिंसाः 10 अक्टूबर 2022 को लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में टाना भगत समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जबरन प्रवेश कर गए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। घटना के कारण न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया था।

उस दौरान स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुरक्षा के लिए एक कमरे में बंद करना पड़ा था। इसके अगले ही दिन 11 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की थी।

घटना होने का इंतजार न करे सरकारः स्वतः संज्ञान से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लातेहार जैसी घटना दोबारा होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को ऐसा सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, जिसमें वे भय, दबाव, धमकी या किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना अपने संवैधानिक और न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

गेतलसूद डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, कभी भी खोले जा सकते हैं फाटक

संवाददाता

रांची,अनगड़ाः क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गेतलसूद डैम के जलस्तर में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। डैम का जलस्तर बढ़कर 1933 आरएल फीट तक पहुँच गया है। विभाग के नियमानुसार जलस्तर 1934 आरएल फीट पर पहुँचते ही डैम के सुरक्षा गेट खोल दिए जाएँगे। मालूम हो कि गेतलसूद डैम की अधिकतम जलभराव क्षमता 1936 आरएल फीट है।

अलर्ट मोड पर संबंधित विभागः जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए संबंधित विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दूसरी ओर, सिकिदिरी स्थित हाइडल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए नहर के माध्यम से लगातार पानी की आपूर्ति की जा रही है।

हुंडरू फॉल और चांडिल डैम में बढ़ेगा जलस्तरः स्वर्णरेखा नदी पर स्थित गेतलसूद डैम के फाटक खोले जाने से निचले इलाकों में पानी का बहाव काफी तेज हो जाएगा। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हुंडरू फॉल का झरना पूरी तरह लबालब भरकर रौद्र रूप ले लेगा। इसके साथ ही स्वर्णरेखा नदी के बहाव से मुरी होते हुए चांडिल डैम तक जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होगी।

तटीय इलाकों में सतर्कता बरतने की अपीलः डैम के गेट खोले जाने की संभावना को देखते हुए नदी के तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों को नदी के तेज बहाव और जलप्रपात के समीप न जाने की हिदायत दी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे या दुर्घटना से बचा जा सके।

झारखंड के 4 शहरों में जल्द चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, सरकार ने केंद्र से मांगी राशि

रांची : झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। सरकार ने चारों शहरों के लिए कुल 400 ई-बसों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत प्रत्येक शहर में 100-100 ई-बसें चलाने का प्रस्ताव है। इनमें स्टैंडर्ड, मिडी और मिनी बसें शामिल हो सकती हैं। ई-बसों की खरीद केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत की जायेगी। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बसों की खरीद और संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

तैयार होगा इंफ्रास्ट्रक्चर : ई-बसों के संचालन से पहले चारों शहरों में जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेगी। इसके तहत बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन, संचालन व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा। बसों के परिचालन के लिए रूट और यात्रियों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने की तैयारीः सरकार का मानना है कि ई-बसों के परिचालन से शहरों में लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी वाहनों पर निर्भरता और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है।

चर्चित कोयला व्यापारी एलबी सिंह के भाई और साले ने ईडी से मांगा समय

रांचीः धनबाद के चर्चित कोयला व्यापारी एलबी सिंह के साले और भाई ने ईडी कार्यालय में हाजिर होने के बदले एक-एक महीने का समय मांगा है। ईडी ने एलबी सिंह के साले रंजीत सिंह को 18 अगस्त और भाई विश्व विजय को 19 अगस्त को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने के लिए समन भेजा था।

ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के दूसरे चक्र के दौरान मिले दस्तावेज की प्रारंभिक जांच के बाद एलबी सिंह के रिश्तेदारों को समन जारी किया है। जांच में पाया गया कि रंजीत सिंह और विश्व विजय सिंह के खाते में बीसीसीएल द्वारा काम के बदले पैसा ट्रांसफर किया गया है। इनके खातों से प्रति दिन औसतन दो-दो करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। रंजीत सिंह के नाम पर 18-20 करोड़ रुपये का फिक्स डिपोजिट पाया गया है।

INVITING REQUEST FOR PROPOSAL(R.F.P.)
WATER RESOURCES DEPARTMENT
GOVERNMENT OF JHARKHAND

NIT NO. : WRD/JH/CE/DMPH/RFP/08/2026

National Competitive Bidding

1.	Name of the Work	Request for Proposal for Conducting Studies and Preparation of Detailed Investigation Reports on Comprehensive Dam Safety Evaluation/ Structural Health Assessment for Dam Rehabilitation/ Preparation of Emergency Action Plan, Operation and Maintenance Manual etc. of Sonua Dam under Chief Engineer, WRD, Ranchi, Water Resources Department, Govt. of Jharkhand
2.	Mode of Submission of Bids	Online through www.jharkhandtenders.gov.in
3.	Tender fee (In INR)	Rs.10,000.00 (Ten thousand only) - ----(Non-refundable)
4.	Bid Security (In INR)	Rs.1,00,000/- (One Lakh only)
5.	Time of completion	150 days from the date of LOA
6.	Date of availability of Bidding Document on Website	18/08/2026;16:00 HRS
7.	Last Date and time of submission of pre-bid queries	25/08/2026;11:00 HRS
8.	Date of Pre Bid Meeting	27/08/2026, 11:30HRS Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002
9.	Last Date of Submission of online Bids	08/09/2026;15:30HRS
10.	Date & time of opening of Technical Bid	09/09/2026;16:30HRS Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002
11.	Name of address of E - procurement officer	Chief Engineer, Design Master Planning And Hydrology, Room No. 203, Second Floor, Jal Bhawan, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002 Email:cedesign-wrd-jhr@nic.in
12.	Helpline no.	9162471847, 09787107524, 09599321224, 09304037930, 09110975717

Note:-Please see details on www.jharkhandtenders.gov.in

PR 387723 Water Resource(26-27).D

Chief Engineer
Design, Master Planning &Hydrology,
Water Resources Department,
Government of Jharkhand

लगातार बारिश से पुंदाग रोड नंबर 3ए अमन ग्रीन सिटी डूबा, टेंडर प्रक्रिया अधर में ,स्थानीय लोग परेशान

मेट्रो रेज

रांची : राजधानी रांची के पुंदाग स्थित रोड नंबर 3ए अमन ग्रीन सिटी क्षेत्र के लोग लगातार बारिश के कारण भारी परेशानी झेल रहे हैं। इस इलाके की मुख्य सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिससे आमजन का आना-जाना दूभर हो गया है।

स्थायी निवासी तौसीफ खान ने बताया कि इस सड़क का निर्माण कार्य लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा रांची नगर निगम के द्वारा इस रोड का टेंडर प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ कागजों में काम की बात होती है जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा।

तौसीफ खान का कहना है कि वे कई बार रांची नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि जल्द ही सड़क निर्माण शुरू होगा। हकीकत यह है कि टेंडर प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, और इलाके की जनता रोजाना गड्ढों व पानी से भरे रास्तों पर चलने को मजबूर है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सड़क पर जमा पानी से गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।

पंच मंदिर तारा नगर में पानी भरने से मार्ग हुआ अवरूद्ध, नगर निगम से कार्रवाई की मांग

रांचीः सामाजिक कार्यकर्ता बीरेंद्र साहु ने कहा कि राँची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 अरगोड़ा पीपर टोली ,नागड़ा ढीपा, तारा नगर आवासीय परिसर स्थित पंच मंदिर तारा नगर में लगातार मूसलाधार बारिश होने पर तारा नगर के कई परिवारों का रास्ता पानी भरने के कारण अवरुद्ध हो गया है। पुंदाग नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लाजपत नगर आवासीय परिसर के परफ से बहती हुई पुंदाग नदी उफान पर है, जिसके चलते पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की महापौर , नगर आयुक्त एवं वार्ड नंबर 36 के वार्ड पार्षद से अनुरोध है कि तारा नगर आवासीय परिसर स्थित पंच मंदिर मार्ग का गार्ड वाल कम से कम तीन फीट ऊंचा करने की योजना बनाई जाये ताकि तारा नगर पंच मंदिर मार्ग के घरों में पानी घुसने से रोका जा सके। जब भी बारिश तेज होती है आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिसकी पिछले साल से ही लगातार राँची नगर निगम के संबंधित अधिकारी, सुपरवाइजर को सूचित किया जाता रहा है। नगर निगम रांची कृपया संज्ञान में लेते हुए इसका समाधान हेतु सकारात्मक पहल करें।

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल,गोंदा,राँची

अतिअल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०–38/2026–27
Email Id – eedwsd.gonda@gmail.com

1.	विभाग का नाम	:–	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची।
2.	विज्ञापनदाता का नाम	:–	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोन्दा, राँची।
3.	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	:–	25.08.2026 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
4.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:–	27.08.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:–	27.08.2026 को अपराह्न 3.30 बजे ।
6.	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	:–	1) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोन्दा,राँची। 2) अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल, राँची।
7.	निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान–	:–	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोन्दा, राँची।
8.	कार्यों की विवरणी	:–	

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	B.O.Q. का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि।
1	Special Repair of Staff Quarter No. C-6 and others Kanke road under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	14,78,954.000	30,000.00	2500.00	1 माह
2	Special repair of staff quarter & Construction of Septic tank with soak pit and its allied work at Qtr No. 02 at Campus of East Jail Road, Ranchi under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	12,68,043.00	25,500.00	2500.00	1 माह
3	Special repair of staff quarter & Construction of Septic tank with soak pit and its allied work at Qtr No. 06 at Campus of East Jail Road, Ranchi under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	13,02,136.00	26,500.00	2500.00	1 माह
4	Construction of Septic tank Soak pit & drain around the Quarter Mis. Works at 6 Nos. P.H.E.D. Quarter s, Bariyatu, Ranchi under D. W. & S. Division, Gonda, Ranchi.	11,61,697.00	23,500.00	2500.00	30 दिन

नियम एवं शर्तें सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

PR 387680 Drinking Water and Sanitation(26-27).D

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल,गोन्दा,राँची

सुविचार

सबसे मुश्किल रास्ता वह होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत भी बनाता है।

वन्दे मातरम् का अपमान करती कांग्रेस को संघ के कार्य से आपत्ति है

राजनीति में जब अपने सवालों का उत्तर देना कठिन हो जाए, तब अक्सर प्रतिपक्ष कोई ऐसा कोना ढूंढ़ता है जिसे कमजोरी के रूप में अपने राजनीतिक विरोधियों के समक्ष इस्तेमाल किया जा सके। शायद, कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों को इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। आखिर जिस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व स्वयं ॠवन्दे मातरम्ॠ के पूरे गान को लेकर उठे गंभीर सवालों के घेरे में है, उसी समय अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कानूनी स्थिति, पंजीकरण, संपत्तियों और वित्तीय पारदर्शिता पर सवालों की बौछार क्यों शुरू हो गई? यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वन्दे मातरम् कोई सामान्य गीत नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, राष्ट्रभाव और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा है। ऐसे में जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों के आचरण को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, तब अपेक्षा यह थी कि कांग्रेस अपने भीतर झांकती, आत्ममंथन करती और अपने नेताओं के आचरण पर स्वयं से प्रश्न करती और अपने आचरण में सुधार करती, किंतु उसके बजाय वह संघ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसमें भी इस पूरे प्रसंग का सबसे रोचक पक्ष यह है कि कांग्रेस के सामान्य कार्यकताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व से बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत की है। जब वन्दे मातरम् का गान हो रहा था, तब अनेक कार्यकर्ता सावधान मुद्रा में खड़े होकर पूरे गान का सम्मान करते दिखाई दिए। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने ही कार्यकताओं से सीखने की आवश्यकता है कि राष्ट्र आराधना किसी राजनीतिक योजना का विषय न होकर यह तो करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रश्न है, जिसका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए। अब आते हैं प्रियांक खरगे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उठाए गए सवालों पर। खरगे पूछ रहे हैं कि संघ किस कानून के तहत अस्तित्व में है? उसका पंजीकरण कहां है? उसकी संपत्तियों का स्वामित्व किसके पास है? बैंक खाते कैसे संचालित होते हैं? ह्यगुरु दक्षिणाह्न के रूप में मिलने वाले योगदान का कानूनी ढांचा क्या है? निश्चय ही किसी भी संगठन की कानूनी और वित्तीय व्यवस्था पर प्रश्न पूछना लोकतंत्र में अपराध नहीं है। मगर प्रश्न पूछने वाले की जिम्मेदारी यह भी है कि वह जिस कानून की दुहाई दे रहा है, पहले उसका अध्ययन करे।

वस्तुतः यहीं सबसे बड़ा आश्चर्य पैदा होता है। प्रियांक खरगे कर्नाटक के गृहमंत्री हैं। उनसे अपेक्षा सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की कोई नहीं करता, इसलिए यह जानना उनका दायित्व है कि भारत में प्रत्येक सामाजिक या स्वयंसेवी समूह के लिए एक ही प्रकार का अनिवार्य पंजीकरण ढांचा नहीं है। संघ समर्थकों का स्पष्ट तर्क है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं को एक स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के रूप में संचालित करता है और उसके लिए किसी एक विशेष केंद्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता नहीं है। अतः अच्छा होता कि वे अपनी बात को ह्यसंघ पंजीकृत है या नहींह्न से आगे बढ़कर यह जानने का प्रयास करते कि आखिर इस विषय में कानून क्या कहता है। दूसरी ओर सच यही है कि संघ को समझना हो तो उसके कागज से पहले उसके कार्य को देखें। वर्ष 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस संगठन की स्थापना की थी, उसका मूल आधार व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन रहता आया है। शाखा संघ के कार्य का बाहरी रूप है, उसके पीछे अनुशासन, आत्मसंयम, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रभाव की अवधारणा है। स्वयंसेवक प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए काम करने की मानसिकता विकसित करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि संघ का वास्तविक प्रभाव उसके कार्यालयों या दस्तावेजों के आगे स्वयंसेवकों की सामाजिक उपस्थिति में दिखाई देता है। जब ओडिशा में 1999 का विनाशकारी चक्रवात आया, जब 2001 में गुजरात भूकंप ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया या जब कोरोना महामारी ने पूरे देश को संकट में डाल दिया, तब स्वयंसेवक राहत कार्यों में दिखाई दिए। भोजन, दवाइयां, रक्त, राहत सामग्री और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने से लेकर अंतिम संस्कार तक अनेक सेवा कार्यों में स्वयंसेवकों ने काम किया और आज भी वे निरंतर देशभर में सेवा कार्य कर रहे हैं। तब किसी पीड़ित ने यह नहीं पूछा कि स्वयंसेवक के पास कौन-सा पंजीकरण प्रमाण-पत्र है। वस्तुतः संघ की राष्ट्रसेवा उसके व्यापक वैचारिक परिवार से जुड़े संगठन जोकि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे हैं में देखी जा सकती है। फिर प्रश्न उठता है, क्या किसी संगठन के सामाजिक योगदान का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर होना चाहिए कि उसके पास कौन-सा सरकारी प्रमाण-पत्र है? यदि संघ के वित्तीय ढांचे पर कोई ठोस कानूनी प्रश्न है तो उसे कानून के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि किसी संपत्ति पर विवाद है तो उसके दस्तावेज सामने आने चाहिए। किंतु सिर्फ इसलिए कि संघ एक विशाल सामाजिक प्रभाव वाला संगठन है, उसके अस्तित्व को संदेह के घेरे में खड़ा कर उसके प्रति लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर किया जाए, यह कहीं से भी नैतिकता नहीं है, जिसकी दुहाई (नैतिकता) आजकल कांग्रेस अक्सर देती हुई दिखाई देती है। संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका हो या 1962 और 1965 के युद्धों के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका, 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में स्वयंसेवकों की भागीदारी जैसे प्रसंग संघ समर्थक आज भी सामने रखते हैं। जिसके बाद इतना तो स्पष्ट है ही कि संघ को भारत के सार्वजनिक जीवन से मिटा देने की कोशिश न तो ऐतिहासिक रूप से संभव है और न सामाजिक रूप से। लगभग एक शताब्दी में संघ ने स्वयंसेवकों का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है जो देश के गांवों, कस्बों और महानगरों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क की शक्ति किसी सरकारी पद से नहीं आती। यह स्वयं के माध्यम से दिनरात की जानेवाली सेवा से आती है। ऐसे में प्रियांक खरगे के लिए शायद सबसे जरूरी प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि ह्यसंघ का पंजीकरण कहां है?ह्न बल्कि यह होना चाहिए कि क्यों करोड़ों भारतीयों के बीच एक गैर-सरकारी, स्वयंसेवी संगठन लगभग सौ वर्षों तक अपना सामाजिक प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा? निश्चित ही इस प्रश्न का उत्तर किसी रजिस्ट्रार के कार्यालय से उन्हें नहीं मिलने वाला है। उत्तर शाखाओं में मिलेगा। स्वयंसेवकों के जीवन में मिलेगा। आपदा के समय किए गए सेवा कार्यों में मिलेगा। दूरदराज के गांवों में चल रहे विद्यालयों में मिलेगा और उन लोगों के अनुभवों में मिलेगा जिन्हें संकट की घड़ी में किसी स्वयंसेवक ने बिना किसी राजनीतिक पहचान पूछे सहायता पहुंचाई।

हां, संघ से सवाल पूछे जाने चाहिए, किंतु वही सवाल हर बड़े सामाजिक और राजनीतिक संगठन से भी पूछे जाने चाहिए। पारदर्शिता की कसौटी समान होनी चाहिए और कांग्रेस के लिए इससे बड़ा आत्ममंथन का अवसर शायद ही कभी आए! आखिर क्यों वह अब तक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ॠवन्देमातरम्ॠ का अनादर करती आ रही है? क्यों नहीं उसने अब तक अपने कार्यालयों में संपूर्ण वन्दे मातरम् के गान को अनिवार्य किया है? क्या कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व को सजा देगी, जोकि सामने आए तमाम वीडियो में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् का अपमान करती नजर आ रही है? अच्छा हो यदि वह कुछ सुधार करना चाहती है तो सबसे पहले स्वयं से सुधार की शुरूआत करे।

आरोप लगा, नौकरी गई, क्या जांच हुई?

> डॉ. सागर ने इन आदेशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका सवाल केवल यह नहीं था कि उन पर क्या आरोप लगाया गया, बल्कि यह भी था कि उस आरोप के आधार पर कार्रवाई किस प्रक्रिया से की गई। उनका कहना था कि आरोप के संबंध में कानून के अनुरूप कोई नियमित विभागीय जांच नहीं की गई। विश्वविद्यालय की ओर से भी इस तथ्य का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका।

भा 12 जून 2026 का दिन डॉ. ममता सागर के लिए शायद यह एक सामान्य कार्यदिवस नहीं था। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉ. सागर की सेवा उसी दिन एक आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके कुछ ही दिनों बाद, 23 जून को, विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार (एस्टेट) ने उन्हें आवंटित आवास खाली करने का निर्देश भी दे दिया। डॉ. सागर ने इन आदेशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका सवाल केवल यह नहीं

अभिषेक शुक्ल

था कि उन पर क्या आरोप लगाया गया, बल्कि यह भी था कि उस आरोप के आधार पर कार्रवाई किस प्रक्रिया से की गई। उनका कहना था कि आरोप के संबंध में कानून के अनुरूप कोई नियमित विभागीय जांच नहीं की गई। विश्वविद्यालय की ओर से भी इस तथ्य का प्रभावी खंडन नहीं किया जा सका। 31 जुलाई 2026 को उच्च न्यायालय ने सेवा समाप्ति और उसके आधार पर जारी आवास खाली करने के दोनों आदेश निरस्त कर दिए तथा विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी। यह कहानी केवल एक कर्मचारी की सेवा समाप्ति की नहीं है। यह उस बुनियादी प्रश्न की ओर ले जाती है जो प्रत्येक अनुशासनात्मक कार्रवाई के केंद्र में होना चाहिए—क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लग जाना ही उसके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई के लिए पर्याप्त है, या निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया भी निष्पक्ष और विधिसम्मत होनी चाहिए? यहीं से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से न हो और जिस व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होने वाले हों, उसे निष्पक्ष, सार्थक और प्रभावी प्रक्रिया का अवसर मिले। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी भी सभ्य विधिक व्यवस्था के मूलभूत तत्व हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति मनमानी न हो तथा उससे प्रभावित व्यक्ति को निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया प्राप्त हो। विशेष रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में, जहां किसी कर्मचारी के सेवा अधिकार, प्रतिष्ठा और आजीविका दांव पर लगी होती है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सिद्धांत प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का समावेश करते हैं तथा शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं।यद्यपि भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि न्यायपालिका ने समय-समय पर अपनी व्याख्याओं के माध्यम से इन्हें संवैधानिक शासन का अभिन्न अंग बना दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रिया केवल विधि द्वारा स्थापित होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तिसंगत होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक निर्णयों को भी प्राकृतिक न्याय के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के मध्य का अंतर समय के साथ काफी हद तक कम हो चुका है। प्राकृतिक न्याय का पहला और सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता (ठीङ्क ख४ीि७,ल्ल उं४२ र४)। इस सिद्धांत का आधार यह धारणा है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। अतः निर्णय लेने वाली प्राधिकारी निष्पक्ष होनी चाहिए तथा उसके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह, पक्षपात अथवा व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। यदि किसी निर्णयकर्ता के संबंध में यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हो जाए कि वह निष्पक्ष नहीं है, तो पूरी कार्यवाही संदेह के घेरे में आ सकती है। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर यह माना है कि पक्षपात की वास्तविक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण पक्षपात की युक्तिसंगत संभावना है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में जनविश्वास बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि वास्तविक निष्पक्षता सुनिश्चित करना। प्राकृतिक न्याय का दूसरा और सर्वाधिक व्यापक सिद्धांत है—अ४िि अ'३ी१ ढं१३ी, अर्थात किसी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह सिद्धांत केवल औपचारिक सुनवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी और सार्थक अवसर प्रदान करने की अपेक्षा करता है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय प्रस्तावित है, उसे आरोपों की स्पष्ट जानकारी दी जाए, आरोपों के समर्थन में प्रयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, विभागीय गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाए तथा अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। दूसरे शब्दों में, सुनवाई का अवसर ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक हो, न कि केवल औपचारिकता निभाने के लिए प्रदान किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को अपने बचाव का प्रभावी अवसर नहीं दिया जाता, तो पूरी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित की जा सकती है। प्राकृतिक न्याय का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक निर्णय कारणयुक्त होना चाहिए। कारणयुक्त आदेश प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण आधार है। जब कोई प्राधिकारी अपने निर्णय के समर्थन में कारण अभिलिखित करती है, तब यह स्पष्ट होता है कि उसने उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों पर समुचित विचार किया है। कारणों का अभाव निर्णय को मनमाना बना सकता है और न्यायिक समीक्षा के दौरान उसे अस्थिर कर सकता है। कारणयुक्त आदेश न केवल प्रभावित व्यक्ति को यह समझने में सहायता करता है कि उसके विरुद्ध निर्णय क्यों लिया गया, बल्कि उच्चतर न्यायिक अथवा प्रशासनिक मंचों को भी निर्णय की वैधता की जांच करने में सक्षम बनाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत किसी कठोर या अपरिवर्तनीय नियम-पुस्तिका का हिस्सा नहीं हैं। वे समय, परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होते रहते हैं। यही कारण है कि न्यायालयों ने उन्हें एक जीवंत अवधारणा के रूप में देखा है, जिसका अंतिम उद्देश्य न्याय की प्राप्ति और अन्याय की रोकथाम है। ए.के. क्रैपाक (अ.ङ. ङ१ंस्रं') के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया था कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और न्याय के विफल होने की संभावनाओं को समाप्त करना है।

अनुशासनात्मक कार्यवाही सामान्यतः किसी शिकायत, सूचना अथवा कर्मचारी के कथित दुराचरण के संज्ञान में आने के पश्चात प्रारम्भ होती है। अधिकांश मामलों में पहला चरण प्रारम्भिक जांच का होता है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। यदि प्रारम्भिक जांच में आरोप असत्य, दुर्भावनापूर्ण अथवा साक्ष्यविहीन पाए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने से इंकार कर सकती है। इसके विपरीत, यदि उपलब्ध सामग्री आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रतीत होती है, तो नियमित विभागीय जांच प्रारम्भ की जाती है।

सपेरा समुदाय के सांस्कृतिक और आर्थिक विस्थापन का विश्लेषण

> यह समुदाय सांपों को 'क्षेत्रपाल' (खेतों का रक्षक) मानता था, क्योंकि वे फसलों को नष्ट करने वाले चूहों का शिकार करते थे। इस प्रकार, नागपंचमी और सपेरों की उपस्थिति ने सदियों तक भारत में सांपों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया, किंतु आज, जब सपेरा गलियों में नहीं दिखता, तो लोग आत्मरक्षा के नाम पर घरों में निकलने वाले सांपों को लाठियों से पीट-पीटकर मार डालते हैं।

भारतीय सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहां प्रकृति, वनस्पति और जीव-जंतुओं को मनुष्य के प्रतिद्वंद्वी के रूप में कभी नहीं देखा गया है। यह सभी तो जीवन के सहयात्री के रूप में हैं। इसी विचार के केंद्र में है भारत की 'नाग संस्कृति'। भगवान शिव के कंठ का आभूषण 'वासुकी' और भगवान विष्णु का शयन-आसन 'शेषनाग' होना इस बात का प्रमाण है कि सनातन संस्कृति ने भयानक समझे जाने वाले जीवों को भी दिव्यता प्रदान की। इस नाग संस्कृति और आम जनमानस के बीच की जीवंत कड़ी रहा है, 'सपेरा समुदाय' (जिन्हें विभिन्न राज्यों में नाथ, जोगी, कालबेलिया या सपेला कहा जाता है)। सदियों से इस घुमंतू समुदाय ने मानव और वन्यजीव के बीच

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

एक ऐसा अनूठा संतुलन बनाया, जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह समझने में असमर्थ है। परंतु, वर्ष 1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के एकतरफा क्रियान्वयन ने इस पूरी विशेषज्ञता को एक झटके में 'अपराध' घोषित कर दिया। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला 'नागपंचमी' का त्योहार एक ओर प्रत्येक हिन्दू के लिए धार्मिक अनुष्ठान है, वहीं दूसरी ओर यह एक गहरी पारिस्थितिक सोच का परिणाम है। वर्षा ऋतु में जब सांप अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तब मनुष्यों और सांपों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है। सनातन परंपरा ने इस टकराव को टालने के लिए 'नागपूजा' का विधान किया। इस विधान के सबसे बड़े पुरोहित सपेरा समुदाय के लोग थे। वे गांवों और शहरों में जाकर लोगों को सांपों के प्रति भयमुक्त करते थे, उनका दर्शन कराते थे और समाज के भीतर एक धार्मिक चेतना जगाते थे कि 'सांप मारने योग्य नहीं, बल्कि पूजनीय जीव है।'

यह समुदाय सांपों को 'क्षेत्रपाल' (खेतों का रक्षक) मानता था, क्योंकि वे फसलों को नष्ट करने वाले चूहों का शिकार करते थे। इस प्रकार, नागपंचमी और सपेरों की उपस्थिति ने सदियों तक भारत में सांपों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया, किंतु आज, जब सपेरा गलियों में नहीं दिखता, तो लोग आत्मरक्षा के नाम पर घरों में निकलने वाले सांपों को लाठियों से पीट-पीटकर मार डालते हैं। यह आधुनिकता की कैसी विडंबना है कि जिस कानून को सांपों को बचाने के लिए लाया गया था, उसी कानून ने सांपों के सबसे बड़े रक्षकों को ही उनसे दूर कर दिया। भारत सरकार ने जब 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम लागू किया, तो उसका उद्देश्य निश्चित रूप से वन्यजीवों की तस्करी और क्रूरता को रोकना था। मगर इस कानून का सबसे क्रूर प्रभाव भारत की अनुमानित 10 से 15 लाख की सपेरा आबादी पर पड़ा। बिना किसी पूर्व तैयारी, बिना किसी वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था और बिना किसी व्यवस्थित पुनर्वास के, सदियों पुराने एक पारंपरिक पेशे को रातों-रात 'गैर-कानूनी' घोषित कर दिया गया। इस कानून के तहत सांपों को अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके कारण सांप को पकड़ना, पास रखना या उसका प्रदर्शन करना 3 से 7 साल की जेल और गैर-जमानती अपराध बन गया। एक घुमंतू समुदाय, जिसके पास न तो खेती के लिए जमीन थी, न स्थायी मकान थे और न ही आधुनिक शिक्षा, वे एक ही झटके में अपनी ही जमीन पर 'अपराधी' बना दिए गए। इस संबंध में ऑल इंडिया घुमंतू सपेरा विकास महासंघ जैसी संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में सपेरा समुदाय के लाखों परिवार घोर गरीबी, भुखमरी और सामाजिक अलगाव के दलदल में धकेल दिए गए। राज्य की नीतियों की आलोचना करते हुए यह प्रश्न उठना अनिवार्य है कि जब एक गरीब सपेरा अपनी आजीविका के लिए सांप रखता है, तो उसे 'क्रूरता' और 'अपराध' कहा जाता है, लेकिन जब वही राज्य 'चिड़ियाघर' या 'सफारी' के नाम पर हजारों जंगली जानवरों को लोहे के पिंजरों में कैद करता है और उनसे व्यावसायिक लाभ (टिकट) कमाता है, तो उसे 'संरक्षण' और 'शिक्षा' का नाम दे दिया जाता है। यह न्याय के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तर्क दिया जाता है कि चिड़ियाघरों में डॉक्टरों की टीम होती है और वैज्ञानिक रखरखाव होता है। परंतु, इस तर्क में सपेरा समुदाय के उस गहन 'पारंपरिक व्यावहारिक विज्ञान' को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसे उन्होंने पीढ़ियों के अनुभव से हासिल किया था। एक सपेरा केवल सांप की फुफकार या मिट्टी पर उसके रेंगने के निशान से उसकी प्रजाति, लिंग और व्यवहार की सटीक जानकारी दे सकता है। क्या किसी आधुनिक विश्वविद्यालय की डिग्री इस व्यावहारिक विशेषज्ञता का मुकाबला कर सकती है? कानून ने इस अनूठे ज्ञान को सहेजने के बजाय उसे नष्ट करना बेहतर समझा। पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा का अपूरणीय सपेरा जाति के पास केवल सांप पकड़ने का हुनर नहीं था, बल्कि उनके पास पारंपरिक औषधियों, जड़ी-बूटियों और सर्पदंश के इलाज का एक अमूल्य मौखिक खजाना था। चूंकि यह समुदाय घुमंतू था, इसलिए इनका ज्ञान किसी लिखित पुस्तक में नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से ट्रांसफर होता था। जब कानून ने इस पेशे पर प्रतिबंध लगाया, तो नई पीढ़ी ने बदनामी और जेल के डर से इस काम से पूरी तरह दूरी बना ली। परिणाम यह हुआ कि वह पारंपरिक ज्ञान, जो भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, हमेशा के लिए लुप्त हो गया। आज जब भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा को पुनर्जीवित करने की बात करता है, तब सपेरा समुदाय के इस नष्ट हो चुके ज्ञान की भरपाई कैसे होगी, इस पर कोई नीति स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपेरा समुदाय के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उनके पुनर्वास का कोई रास्ता नहीं था। इसका सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण तमिलनाडु की 'इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी' है। जब 1972 के कानून से इरुला जनजाति की आजीविका छिनी, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद रोमुलस व्हिटेकर के प्रयासों से सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। सरकार ने इरुला समुदाय के लोगों को कानूनी रूप से सांप पकड़ने और उनका जहर निकालने का लाइसेंस दिया। आज, भारत में सांप के काटने से बचने वाली जीवन रक्षक दवाएं बनाने के लिए 80% से अधिक जहर यही इरुला समुदाय अपनी विशेषज्ञता से निकालता है। इस सहकारी समिति से उन्हें सम्मानजनक रोजगार भी मिला और देश को जीवन रक्षक दवाएं भी। प्रश्न यह उठता है कि जो मॉडल तमिलनाडु के इरुला समुदाय के लिए सफल रहा, उसे उत्तर भारत के नाथ, जोगी और कालबेलिया सपेरा समुदायों के लिए पूरे देश में व्यापक स्तर पर क्यों नहीं लागू किया गया? उत्तर भारत के सपेरों को इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से क्यों नहीं जोड़ा गया? यह राज्य तंत्र की प्रशासनिक उदासीनता और नीतिगत विफलता का एक बड़ा प्रमाण है।

कल्कि जयंती 2026: कलयुग के अंत और सत्य युग की स्थापना का प्रतीक

हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती मनाई जाती है। इस बार आज यानी की 18 अगस्त 2026 को कल्कि जयंती मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि कलियुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम कल्कि अवतार लेंगे। मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। तो आइए जानते हैं कल्कि जयंती की तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में...

सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरूआत होगी। वहीं आज यानी की 18 अगस्त की शाम 05:50 मिनट पर इस तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से 18 अगस्त 2026 को कल्कि जयंती मनाई जाएगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 04:31 बजे से शाम 05:50 बजे तक है।

पौराणिक मान्यताएं

पौराणिक ग्रंथों जैसे अग्निपुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, कल्कि पुराण, वायुपुराण के मुताबिक कलियुग के अंतिम चरण में 'शंभल' नामक जगह पर विष्णुयश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतरण होगा। वह देवदत्त नामक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे। भगवान कल्कि पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। सिर्फ हिंदू धर्मग्रंथों में ही नहीं बल्कि सिख और बौद्ध धर्म में भी भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है।

पूजन विधि

कल्कि जयंती के दिन भगवान श्रीहरि के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। वहीं भक्त इस दिन व्रत भी करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें और लकड़ी की चौकी पर लाल या पील कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु या भगवान कल्कि के मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, कुमकुम और हल्दी का तिलक करें। फिर ताजे फूल अर्पित करें और धूप-दीप, नैवेद्य अर्पित करें और तुलसी दल नैवेद्य में जरूर रखें। पूजा के अंत में आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और या कल्किपुराण का पाठ करें। साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप करें।

टिप्स

स्वस्थ बचपन के लिए महत्वपूर्ण विटामिन सी

विटामिन सी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, आयरन के अवशोषण में सहायता करने और बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। चूंकि शरीर स्वयं बड़ी मात्रा में विटामिन सी का संश्लेषण या भंडारण नहीं कर सकता, इसलिए बच्चों को यह पोषक तत्व प्रतिदिन अपने आहार के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है – जो त्वचा, हड्डियों, उपास्थि, स्नायुबंधन और रक्त वाहिकाओं के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन है। यह एक ऐसा पोषक तत्व भी है जो घाव भरने में सहायक होता है और शरीर में ऊतकों के सामान्य विकास को बनाए रखता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है, जिससे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा, विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह पोषक तत्व पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों से आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है, जिससे आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का खतरा कम हो जाता है, जो बच्चों में काफी आम समस्या है। एनआईएच की सिफारिशों के अनुसार, विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता है : 1–3 वर्ष की आयु के बच्चे : लगभग 15 मिलीग्राम, 4–8 वर्ष की आयु के बच्चे : लगभग 25 मिलीग्राम व 9–13 वर्ष आयु के बच्चे : लगभग 45 मिलीग्राम।आवश्यक विटामिन सी की अधिकांश मात्रा हरी सब्जियों और ताजे फलों से भरपूर आहार के माध्यम से पूरी की जा सकती है। कई आम खाद्य पदार्थों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और यदि उन्हें सही तरीके से तैयार किया जाए तो वे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं।

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।
प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website : www.metrorays.in**
email : metrorays.ranchi@gmail.com

बासकीनाथ में जांच के बाद खुला बड़ा राज

श्रावणी मेला में धड़ल्ले से हो रही है मिलावटी सामानों की बिक्री

संवाददाता

बासुकीनाथः राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में सोमवार को मंदिर के समीप, शिवगंगा रोड एवं समर्पण चौक स्थित विभिन्न पेड़ा दुकानों और भोजनालयों सहित कुल 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गयी।

मोबाइल लैब से 60 नमूनों की जांचः मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से जांच के दौरान पेड़ा, दही, हल्दी, सब्जी, सेव सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 60 नमूनों की मौके पर ही

जांच की गयी। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अनियमितता पाये जाने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 38 किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट कराया। इसके अलावा पैकेट में बंद एक्सपायर्ड दही भी नष्ट कराया गया।

जांच करते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लगा जुर्मानाः खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 6500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति रही। जांच के लिए भेजा जायेगा पेड़ा का सैंपलः एफएसओ ने बताया कि जांच के दौरान पेड़ा का नमूना संग्रहित किया गया है, जिसे विस्तृत जांच के लिए खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देशः जांच अभियान में एफएसओ अंजना रानी मिंज, एफएसओ डेजी नीलिमा तिग्गा, जरमुंडी थाना पुलिस बल, एमएफटीएल के जूनियर एनालिस्ट शुभम कुमार एवं लैब अटेंडेंट सुधांश कुमार मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा टीम ने कारोबारियों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने, एक्सपायर्ड एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

नौ दिवसीय शिव कथा का शुभारंभ

घाटजमनी पंचायत में 501 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभायात्रा

संवाददाता

साहिबगंज /राजमहलःप्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घाटजमनी पंचायत स्थित नमामि गंगे घाट पर सावन माह के तीसरी सोमवारी से शुरू होने वाले शिव कथा के अवसर पर 501 कन्याओं व महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। जहां गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।उधर यह कलश शोभायात्रा नमामि गंगे घाट से प्रारंभ होकर सरकंडा,सेलमपुर,टपुवा और बुधवरिया होते हुए चंडीपुर पहुंची जहां इसके बाद यात्रा वापस में नमामि गंगे घाट पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।वही शिव कथा का वाचन अयोध्या धाम से पधारे कथा वाचक धनंजय वैष्णव

जी महाराज के द्वारा किया जाएगा।जहां नौ दिवसीय शिव कथा का शुभारंभ सोमवार से हुआ।जो लगातार नौ दिनों तक चलेगी।वही कथा के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और धार्मिक प्रसंगों का श्रवण कराया जाएगा।वही कलश शोभायात्रा एवं कथा आयोजन के मौके पर सोमल चौरसिया,सुजीत चौरसिया,विनाद चौरसिया,ऋषिकेश चौरसिया,अरुण चौरसिया,रमेश यादव,बीरबल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु मौजूद थे।

फलदार पौधों के वितर ा के साथ दिया पर्यावर ा संरक्ष ा का संदेश

संवाददाता

साहिबगंजःगंगा मिशन कोलकाता-साहिबगंज की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधरोपण और फलदार पौधों के वितरण का अभियान चलाया जा रहा है।इसी क्रम में 17 अगस्त सोमवार को भारतीय रोड स्थित बाबूलाल नंदलाल बोहरा ट्रस्ट परिसर में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया।कार्यक्रम में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, बंगाली टोला,नगर पालिका कन्या मध्य विद्यालय,साहिबगंज और तालाब मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद की उपाध्यक्ष विनीता देवी ने अपने हाथों से विद्यार्थियों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया। जबकि उन्हें अधिक से अधिक

पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर गायत्री परिवार के कल्याण श्रीवास्तव,संजीव चौधरी, ओम प्रकाश सिन्हा,पूर्व वार्ड सदस्य बासुकीनाथ यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका रानी झा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पेड़-पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य का आधार हैं।उन्होंने विद्यार्थियों से पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की।

गंगा मिशन के इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में अधिक से अधिक पौधारोपण को प्रोत्साहित करना है।

इग्नू में जुलाई 2026 सत्र के लिए नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ी

संवाददाता

साहिबगंजः-इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, देवघर के निदेशानुसार इग्नू अध्ययन केंद्र-3605, साहिबगंज महाविद्यालय के समन्वयक डॉ।ध्रुव ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2026 सत्र में नव नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2026 तक कर दी गई है। इच्छुक

विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं।उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए पीजी,यूजी,डिप्लोमा एवं विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रम उपलब्ध हैं। जुलाई 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया भी 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से जारी है।डॉ।सिंह ने कहा कि इग्नू देश का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है, जहाँ कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण एवं यूजीसी मान्यता प्राप्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।नौकरी या अन्य कार्यों के साथ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक उत्कृष्ट विकल्प है।यहाँ स्व-अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन अध्ययन संसाधन, लचीली अध्ययन व्यवस्था तथा देशभर में अध्ययन एवं परीक्षा केंद्रों की सुविधा उपलब्ध है।इग्नू की डिग्रियाँ उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए पूर्णतः मान्य हैं।उन्होंने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र अपना नामांकन एवं पुनः पंजीकरण सुनिश्चित करें।

दुमका के छात्रों को बड़ी सौगात

7.54 करोड़ से बनेगा आधुनिक पुस्तकालय, बदलेगी तस्वीर

संवाददाता

दुमकाः जिले के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दुमका में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेट ऑफ द आर्ट जिला पुस्तकालय का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 7 करोड़ 54 लाख 53 हजार 871 रुपये का टेंडर जारी किया है। एजेंसी को निर्माण कार्य 365 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मिलेगा लाभः स्टेट ऑफ द आर्ट जिला पुस्तकालय के निर्माण से जिले के विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधायें मिलने की उम्मीद है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह पुस्तकालय उपयोगी साबित हो सकता है। आधुनिक

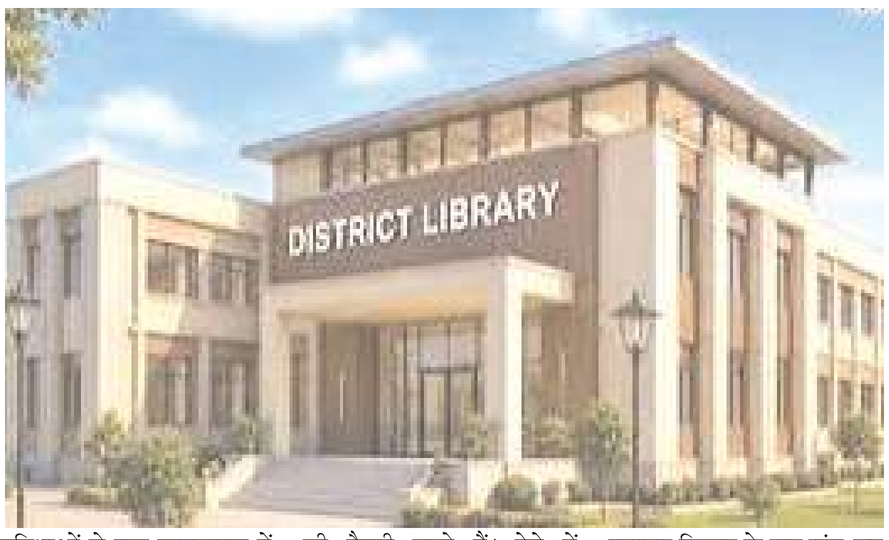

सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय में विद्यार्थियों को शांत और व्यवस्थित अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराने की योजना है। दुमका संताल परगना का प्रमंडलीय मुख्यालय और प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। जिले में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा मिलने से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। राजकीय पुस्तकालय में भी पहुंचते हैं 500 से अधिक विद्यार्थीः दुमका में राजकीय पुस्तकालय भी है, जहां पिछले पांच साल में सुविधाओं के लगातार विस्तार के बाद पांच-छह सौ विद्यार्थी नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में आधुनिक जिला पुस्तकालय का निर्माण शैक्षणिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिले के विद्यार्थियों को अध्ययन, संदर्भ सामग्री और पुस्तक संबंधी सुविधाओं के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें घर पर अध्ययन के लिए पर्याप्त संसाधन या अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है।

श्रीरामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय परिसर में निर्माण की उम्मीदः प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जिला पुस्तकालय के निर्माण के लिए श्रीरामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय परिसर में खाली पड़ी जमीन का चयन किया गया है। विद्यालय परिसर में पहले से ही कई विकास कार्य चल रहे हैं। प्लस टू में उत्क्रमित होने के बाद एक ओर जहां विद्यालय में अतिरिक्त वर्गकक्षों का निर्माण हो रहा है, वहीं डायट के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, हॉस्टल और क्वार्टर का निर्माण भी कराया जा रहा है। अब इसी परिसर में आधुनिक जिला पुस्तकालय के निर्माण की चर्चा है। बता दें कि स्कूल का परिसर कुल 17 बीघा और 17 कट्ठे में फैला हुआ है।

एकलव्य फिटकोरिया में भी बनेगा पुस्तकालयः दुमका जिले के काठीकुंड में संचालित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फिटकोरिया में भी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गयी है। इसके लिए 11 लाख 81 हजार 710 रुपये की लागत से टेंडर निकाला गया है। पुस्तकालय निर्माण का काम तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

दो साल पहले ही इस स्कूल का संचालन शुरू हुआ है। पुस्तकालय सहित अन्य संसाधनों की कमी को दूर करने की दिशा में अब पहल की जा रही है। पुस्तकालय बनने से स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए किताबें और अध्ययन का बेहतर माहौल मिलने की उम्मीद है।

न्यूज IN ब्रीफ

बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान

साहिबगंजःजिला समाज कल्याण पदाधिकारी के निदेशानुसार उत्क्रमित उच्च बालिका विद्यालय तालझारी में किशोरियों की शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य व सशक्तिकरण को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ बाल विवाह मुक्त भारत बाल संरक्षण पीसीएसओ एक्ट गुड टच-बैड टच डिजिटल साक्षरता मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन? डायन प्रथा और सखी वन स्टॉप सेंटर सहित विभिन्न विषयों पर बालिकाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बालिकाओं को बाल विवाह की रोकथाम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हिंसा अथवा संकट की स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी देते हुए 1098 प्रायोजन योजना आफ्टर केयर व फोस्टर केयर जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। जबकि किशोरियों द्वारा एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। उन्हें सेनेटरी पैड का वितरण भी किया गया।कार्यक्रम का संचालन संरक्षण पदाधिकारी गैर-संस्थागत देखरेख चंदा कुमारी ने किया। उन्होंने किशोरियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-मोहम्मद खालिद जिला समन्वयक मंथन अमन वर्मा परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन मो। इकबाल विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य शिक्षकगण सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

राजस्व भू-अर्जन योजनाओं की मासिक समीक्षा, राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता व गति लाने का निर्देश

साहिबगंजः जिला अंतर्गत राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति एवं कार्य प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक की शुरूआत में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 9009।00 लाख के विरुद्ध 3549।41 लाख रुपये 35।82 राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी गई। उत्पाद विभाग ने 1022।00 लाख रुपये की राजस्व प्राप्त कर 33।77% लक्ष्य प्राप्त किया। परिवहन विभाग ने 32।85% राजस्व प्राप्त किया। राजमहल नगर पंचायत ने 51।78% तथा बरहरवा नगर पंचायत 47।44% लक्ष्य प्राप्त की। मत्स्य विभाग द्वारा 58।24% तथा विद्युत बोर्ड द्वारा 38।94% लक्ष्य प्राप्त किया गया।उन्होंने अंचलावार ऑनलाइन जाति, निवास आय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा की गई। विभिन्न सेवाओं में लंबित 10,296 आवेदन 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदन इसमें शामिल हैं। उपायुक्त के द्वारा सभी संबंधित अंचलाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया । बैठक के दौरान भू-लगान एवं भू-सेस, दाखिल-खारिज, परिशोधन, एवं भूमि अधियाचना से संबंधित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुँच सके।उन्होंने भू अर्जन से संबंधित मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 80 पैकेज 02 के मुआवजा भुगतान एवं संरचना वृक्ष हेतु पदाधिकारियों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता विजय कुमार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत कार्यकारी एजेंसी उपस्थित थे।

नवलशाही से बोल बम के जयघोष के साथ बाबाधाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

मेट्रो रेज संवाददाता

डोमचांच (कोडरमा)ः सावन के पावन अवसर पर मंगलवार को नवलशाही कालीमंडा प्रांगण से दर्जनों कांवरियों का जत्था बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण ट्रेडर्स सह भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नवलशाही कृष्णा साव की ओर से किया गया। इस दौरान कांवरियों को बोल बम लिखी टी-शर्ट सहित अन्य सामग्री भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके बाद गेरुआ झंडा दिखाकर सभी कांवरियों को बाबानगरी देवघर के लिए रवाना किया गया। रवानगी के दौरान पूरा कालीमंडा परिसर हर। हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कृष्णा साव ने भगवान भोलेनाथ से समस्त ग्रामवासियों के सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति की मंगलकामना की। मौके पर उपमुखिया शकुंतला देवी सहित मोनू यादव, निरंजन पाण्डेय, धीरज शर्मा, महादेव ठाकुर, संदीप साव, लक्ष्मण साव, आशीष साव, दशरथ यादव, भोला ठाकुर, संतोष गुप्ता, प्रदीप ठाकुर, मधुसूदन पाण्डेय समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कांवरियों के जत्थे के रवाना होते ही माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया।

विश्व कप हिस्सेदारी बेचने की योजना की आलोचना के बाद फीफा ने सीओओ लामूर को हटाया

एजेंसी

नई दिल्ली : विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने अपने मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) केविन लामूर से नाता तोड़ लिया है। यह घटनाक्रम फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की विश्व कप में हिस्सेदारी निवेशकों को बेचने की योजना की लामूर द्वारा आलोचना किए जाने के बाद सामने आया है। फीफा के कर्मचारियों को संगठन के महासचिव मटियास ग्राफस्ट्रोम की ओर से ईमेल के जरिए इस फैसले की जानकारी दी गई। ईमेल में कहा गया कि फीफा और लामूर ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।

बीबीसी स्पोर्ट्स के अनुसार, फीफा के प्रवक्ता ने कहा, ह्लमुख्य संचालन अधिकारी के रूप में फीफा और केविन लामूर के बीच कार्य संबंध 17 अगस्त 2026 को

समाप्त हो गया। फीफा उनकी दो साल की सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद करता है और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। लामूर का जाना ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने इन्फेंटिनो की विश्व कप की हिस्सेदारी निवेशकों को बेचने की योजना पर खुलकर सवाल उठाए थे। योजना को बाद में यूईएफए, एएफसी और कॉनकाकाफ समेत कई प्रमुख फुटबॉल संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इन्फेंटिनो ने छोड़ दिया था। लामूर ने इस योजना को ह्लएक व्यक्ति की परियोजनाह्व करार दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस योजना को लेकर फीफा प्रशासन को ह्लगुमराहह्व किया गया। उन्होंने कहा था, ह्लहमारा मिशन–फीफा के सैकड़ों समर्पित और जुनूनी कर्मचारियों का मिशन–फुटबॉल की सेवा करना है। एक अध्यक्ष को लोगों को साथ लाना, एकजुट करना और प्रेरित करना चाहिए। आज हम इसके विपरीत स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। लामूर ने अपनी नौकरी जाने की संभावित आशंका पर भी स्पष्ट रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था, ह्लअगर इसका मतलब है कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, तो ऐसा ही सही। मैं उस फैसले को समझूंगा और उसका सम्मान करूंगा। कम से कम उस रात मैं चैन से सो पाऊंगा। विश्व कप हिस्सेदारी बेचने की योजना को लेकर यूईएफए, कॉनकाकाफ और एएफसी ने भी फीफा पर गंभीर आरोप लगाए थे।

सिनसिनाटी ओपन: पहले दौर में हारीं विलियम्स बहनें, कोस्त्युक-स्टियर्न्स की जोड़ी ने दी मात

सिनसिनाटी : टेनिस की दिग्गज बहनें वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स सिनसिनाटी ओपन के महिला युगल के दूसरे दौर में पहुंचने से महज दो अंक दूर रह गईं। सोमवार को खेले गए पहले दौर के मुकाबले में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और स्थानीय खिलाड़ी पेटन स्टियर्न्स ने विलियम्स बहनों को 2–6, 6–1, 10–8 से हराया। यह मुकाबला सेरेना और वीनस की 2022 अमेरिकी ओपन के बाद पहली बार साथ में प्रतिस्पर्धी मैच था। दोनों बहनों ने तीन सेट के रोमांचक मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाई, लेकिन निर्णायक सुपर टाईब्रेक में जीत से दो अंक दूर रह गईं। विलियम्स बहनों को सिनसिनाटी ओपन में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश मिला था। यह टूनार्मेंट अमेरिकी ओपन की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो छह दिन बाद शुरू होने वाला है। पहले सेट में सेरेना और वीनस ने दमदार खेल दिखाते हुए 6–2 से जीत दर्ज की। हालांकि, कोस्त्युक और स्टियर्न्स ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की और 6–1 से सेट अपने नाम कर मुकाबले को निर्णायक सुपर टाईब्रेक में पहुंचा दिया।

सिनसिनाटी ओपन: ज्वेरेव ने अटमाने को हराकर चौथे दौर में बनाई जगह

एजेंसी

सिनसिनाटी : जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सिनसिनाटी ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। ज्वेरेव ने कड़े मुकाबले में सोमवार को फ्रांस के टेरेन्स अटमाने को 7-6(4), 7-6(8) से हराया। दूसरे सेट के टाईब्रेक में ज्वेरेव के पास 6-4 के स्कोर पर दो मैच प्वाइंट थे। अटमाने ने पहले मैच प्वाइंट पर शानदार ऐस लगाकर बचाव किया, जबकि दूसरे पर ज्वेरेव ने डबल फॉल्ट कर दिया और स्कोर 6-6 हो गया। हालांकि, 29 वर्षीय जर्मन खिलाड़ी ने इसके बाद लगातार दो अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उन्होंने दो घंटे नौ मिनट में सीधे सेटों में जीत दर्ज की। इस बीच 19 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी राफेल जोदार ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अलेजांद्रो

टेबिलो को 6-2, 6-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। जोदार ने महज 75 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। वह इस दशक में सिनसिनाटी में राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाले कार्लोस अल्काराज और बेन शेल्टन के बाद तीसरे किशोर खिलाड़ी बन गए हैं। कोबोली ने कड़े मुकाबले में अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को 7-5, 4-6, 7-5 से हराया। निर्णायक सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद इटली के 24 वर्षीय खिलाड़ी ने लगातार चार गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। फिल्स ने नौवीं वरीयता प्राप्त लेहेका को चौंकाया अन्य मुकाबले में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने नौवीं वरीयता प्राप्त जिरी लेहेका को 6-1, 6-7(7), 6-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। दूसरे सेट के टाईब्रेक में फिल्स के पास 7-6 पर मैच प्वाइंट था, लेकिन लेहेका ने उसे बचाकर मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया। फिल्स ने दो घंटे एक मिनट में जीत दर्ज की।अब फिल्स का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनॉर से होगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बारिश के कारण तीन बार बाधित हुए मुकाबले में आर्थर फेरी को 7-5, 7-6(3) से हराया। डी मिनॉर दूसरे सेट में एक समय 5-1 से आगे थे, लेकिन फेरी ने लगातार छह गेम जीतकर 6-5 की बढ़त बना ली। हालांकि, डी मिनॉर ने दबाव में धैर्य बनाए रखा और टाईब्रेक में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीधे सेटों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

इमरान हाशमी ने ली आवारापन से 10 गुना ज्यादा फीस! दिशा और शबाना आजमी की फीस भी आई सामने

इमरान हाशमी की कल्ट क्लाकिस फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। फिल्म में दिशा पटानी और शबाना आजनी भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। जानिए इन एक्टर्स ने फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज की है। फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है। फिल्म की रिलीज से पहले अब इसकी स्टारकास्ट की कथित फीस को लेकर भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी को 'आवारापन 2' में अपने आइकॉनिक किरदार शिव पंडित को दोबारा निभाने के लिए करीब 12 करोड़ रुपये फीस दी जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फीस उन्हें 2007 में आई पहली फिल्म 'आवारापन' के लिए मिली रकम से करीब 10 गुना ज्यादा है।

दिशा पटानी की फीस कितनी

फिल्म में दिशा पाटनी भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें 'आवारापन 2' के लिए करीब 5 करोड़ रुपये फीस मिल रही है। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी 'आवारापन 2' का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म में अहम भूमिका निभाने के लिए उन्हें करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच फीस दी गई है।

फिलहाल ये सभी फीस के आंकड़े रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और मेकर्स या कलाकारों की तरफ से इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'

'आवारापन 2' में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंथ कोहली, अनिरुद्ध रावल और अतुल कुमार भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म का म्यूजिक मिथून, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा ने दिया है, जबकि डायरेक्शन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं।

रुक्मिणी वसंत ने निन पाउली के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की शुरू

रुक्मिणी वसंत का करियर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा! एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स के साथ अब एक्ट्रेस ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, यानी उनकी बढ़ती–चढ़ती फिल्मोग्राफी में एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की एंट्री हो गई है। हाल ही में रुक्मिणी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के क्लैपबोर्ड की एक झलक शेयर करते हुए शूटिंग शुरू होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। इस अनटाइटल्ड मलयालम फिल्म में रुक्मिणी के साथ मलयालम स्टार निन पाउली नजर आएंगे। यानी साउथ के दो टैलेंटेड स्टार्स का ये कॉम्बिनेशन पहले से ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेट से एक झलक शेयर करते हुए रुक्मिणी ने लिखा, 'और बस, ये सफर शुरू हो गया।

किसी ऐसी जगह का हिस्सा बनना, जिसे आपने इतने लंबे समय तक दूर से निहारा और सराहा हो, अपने आप में बेहद खास एहसास है। और अब उसी जगह का एक छोटा सा हिस्सा बन पाना मेरे लिए वाकई बहुत स्पेशल फर्स्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ '। अब फिल्म की टीम भी इसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है। इस प्रोजेक्ट को चार्ली और नयद्ब जैसी शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर–प्रोड्यूसर मार्टिन प्रक्कट का सपोर्ट मिला है। वहीं जय जय जय जय जय हे के राइटर्स में शामिल रहे नाशिद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। रुक्मिणी वसंत और निन पाउली के साथ इन नामों का जुड़ना ह्रक्क1 को मलयालम सिनेमा की मोस्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग फिल्मों में से एक बना रहा है। सप्त सागरदाचे एलो और कंतारा जैसी फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से रुक्मिणी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी सिर्फ एक प्रॉमिसिंग कन्नड़ टैलेंट के तौर पर देखी जाने वाली रुक्मिणी अब धीरे–धीरे पूरे साउथ इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा डिमांड वाली यंग एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बना चुकी हैं। रुक्मिणी अब टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन–अप्स को लेकर भी तैयार हैं। इसके अलावा उनके खाते में मच–अवेटेड बिग–टिकट फिल्म ड्रैगन भी है। शानदार परफॉर्मेंस, अलग–अलग तरह के किरदार और बड़े पैन–इंडियन प्रोजेक्ट्स के साथ रुक्मिणी का करियर फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनका ये नया मलयालम प्रोजेक्ट उनकी तेजी से शानदार होती करियर जर्नी में एक और एक्साइटिंग चैप्टर जोड़ता नजर आ रहा है।

पति हिमांशु मल्होत्रा संग तलाक की खबरों पर फूटा अमृता खानविलकर का गुस्सा

अभिनेत्री अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा काफी वक्त से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। बी–टाउन में काफी वक्त से ऐसी अटकलें लग रही हैं कि इनके रिश्ते में दरार आ गई है और तलाक हो रहा है। इन्हें अमृता ने निराधार बताया है। साथ निजी जिंदगी को लेकर ऐसी अफवाहें प्रसारित करने वालों को भी चेताया है।

लीगल टीम ने जारी की चेतावनी

अभिनेत्री अमृता के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें उनकी लीगल टीम की तरफ से इस तरह की खबरों को एकदम निराधार बताया गया है। साथ ही अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है।

अमृता की कानूनी टीम ने नोट साझा करते हुए लिखा है, 'आधिकारिक कानूनी बयान – 10 अगस्त 2026 से लागू। हमारे ध्यान में आया है कि कुछ ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अमृता खानविलकर और उनके निजी जीवन के बारे में ऐसा कंटेंट फैला रहे हैं, जो बेबुनियाद है। यह प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। आगे लिखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन अमृता खानविलकर के बारे में मानहानि वाले बयान, अफवाहें, बिना पुष्टि वाले आरोप या गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने या शेयर करने के लिए इस स्वतंत्रता का कोई भी गलत इस्तेमाल गंभीरता से लिया जाएगा। जहां भी उपलब्ध सबूतों से पुष्टि होती है, वहां ऐसे कंटेंट को बनाने, फैलाने या शेयर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों के खिलाफ लागू कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे सभी मामलों पर नजर रखी जा रही है और उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

मराठी फिल्म जगत की चर्चित अभिनेत्री अमृता खानविलकर की शादी हिमांशु मल्होत्रा के साथ साल 2015 में हुई थी। दोनों की मुलाकात साल 2004 में हुई थी। लंबे वक्त तक दोनों रिलेशनशिल में रहे। फिर साल 2015 में शादी का फैसला लिया।

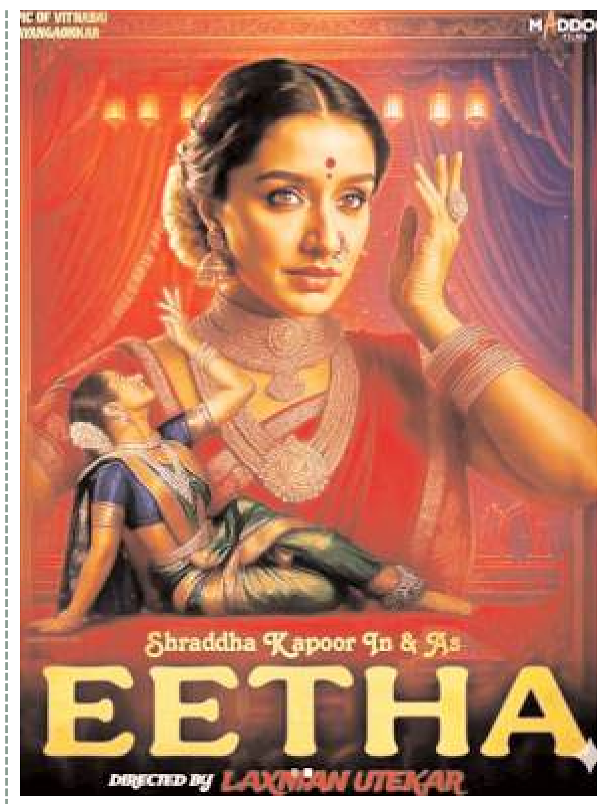

'टॉक्सिक' से नहीं होगी 'ईठा' की टक्कर आयुष्मान की 'उड़ता तीर' की भी रिलीज डेट अनाउंस

बॉलीवुड की दो मच अवेटेड फिल्मों की रिलीज डेट मेकर्स ने अनाउंस की। जहां एक और आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट तय की। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली। अब ये दोनों फिल्में कब रिलीज होंगी

कब रिलीज होगी फिल्म 'ईठा'

श्रद्धा कपूर की बहुप्रतिक्षित फिल्म 'ईठा' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म लावणी साम्रज्ञी विठाबाई नारायणगावकर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पांच दशक तक लावणी लोककला को अपना जीवन समर्पित किया। 'टॉक्सिक' से टाला क्लैश पहले यह फिल्म इसी महीने 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, जहां इसकी टक्कर 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही मल्टीस्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' से होती। अब मेकर्स ने इसे 4 दिसंबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। फिल्म में श्रद्धा के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

सिनेमाघर में प्रभास की फिल्म में होगा सामना

भले ही फिल्म 'ईठा' ने 'टॉक्सिक' से टकराव बचा लिया है पर 4 दिसंबर को इसका टकराव प्रभास की फिल्म 'फौजी' से होगा। फिलहाल 'फौजी' की रिलीज डेट 3 दिसंबर 2026 है। 'फौजी' का निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है। फिल्म की कास्ट में प्रभास के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर भी हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म 'उड़ता तीर'

फिल्म 'उड़ता तीर' से आयुष्मान खुराना और सारा अली खान एक बार फिर पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। यह एक स्पाई–कॉमेडी फिल्म है जो 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन आकाश ए. कौशिक ने किया है। वहीं फिल्म में निर्माताओं की लंबी लिस्ट है। फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन मिलकर कर रहे हैं।

शुभेंदु सरकार के 100 दिन: सीमा सुरक्षा से चटकलों, अन्नपूर्णा-आयुष्मान से निवेश तक बहुत कुछ बदला

एजेंसी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को अपने 100 दिन पूरे कर लिए। सरकार ने इन 100 दिनों की उपलब्धियों का विभागवार लेखा-जोखा तैयार किया है। सत्ता पक्ष इसे चुनावी वादों को तेजी से जमीन पर उतारने का उदाहरण बता रहा है। वहीं, कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की संख्या और जमीनी असर को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार के पहले 100 दिनों को देखें तो सीमा सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, बंद चटकलों को खोलना, महिलाओं को आर्थिक सहायता, केंद्रीय योजनाओं का विस्तार और निवेश आकर्षित करना प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने आते हैं।

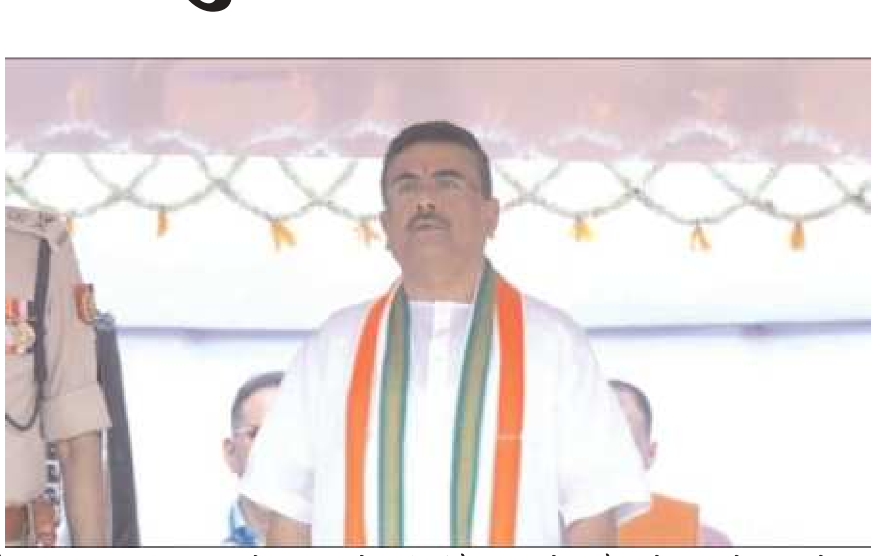

शुभेंदु सरकार की सबसे चर्चित पहल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला शामिल है। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही थी कि राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण कई हिस्सों में सीमा पर बाड़ लगाने का काम अटका हुआ है। सत्ता में आने के बाद नई सरकार ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीएसएफ को बड़े पैमाने पर जमीन हस्तांतरित की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के नौ सीमावर्ती जिलों में 767 एकड़ से अधिक जमीन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को दी जा चुकी है, जबकि करीब 362 एकड़ अतिरिक्त जमीन के हस्तांतरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह बीएसएफ को उपलब्ध कराई गई जमीन का कुल क्षेत्रफल 1100 एकड़ से अधिक हो गया है। सीमा सुरक्षा के लिए दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 44 एकड़ से अधिक जमीन सशस्त्र सीमा बल को भी दी गई है। दार्जिलिंग में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन का मुख्यालय बनाने के लिए करीब 110 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम बता रही है। भूमि विभाग ने आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने में तेजी दिखाई है। सेवक-रंगपो ब्रॉडगेज रेल परियोजना के लिए रेलवे को 20 एकड़ जमीन दी गई है। पश्चिम मेदिनीपुर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए करीब छह एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सरकारी गोदाम, बिजली उपकेंद्र और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए भी जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज की गई है। सरकार के 100 दिनों की सबसे चर्चित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में चिंगड़ीघाटा मेट्रो परियोजना का काम भी शामिल है। लंबे समय से अटका यह काम नई सरकार के निर्देश के बाद तेजी से आगे बढ़ा। निर्माण एजेंसी आरवीएनएल के साथ समन्वय करते हुए मई में दो सप्ताहांत पर चिंगड़ीघाटा मोड़ पर यातायात नियंत्रित किया गया और वायाडक्ट लगाने का काम पूरा किया गया। इसके बाद बेलेघाटा और गौरकिशोर घोष स्टेशनों के बीच रेल संपर्क का काम आगे बढ़ा। भाजपा इसे प्रशासनिक इच्छाशक्ति का उदाहरण बता रही है। रोजगार के मोर्चे पर बंद चटकलों को दोबारा खोलने का दावा सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में है। श्रम विभाग के अनुसार, हुगली नदी के दोनों किनारों पर पिछले 100 दिनों में 16 बंद चटकलें दोबारा खुली हैं। सरकार का दावा है कि इससे 35 हजार से अधिक श्रमिकों की आजीविका फिर से सुरक्षित हुई है। लंबे समय से संकट से जूझ रहे राज्य के जूट उद्योग के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिवहन क्षेत्र में भी सरकार ने चुनावी वादे को लागू करने की कोशिश की है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की गई है। इसके साथ ही कई मार्गों पर नई सरकारी बसें उतारी गई हैं। हालांकि, सरकारी बसों की संख्या अभी भी जरूरत के मुकाबले कम होने की बात कही जा रही है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए आगे और बड़े कदम उठाने की चुनौती सरकार के सामने है।

महिलाओं के लिए ह्यअन्नपूर्णा योजनाह्न सरकार की प्रमुख चुनावी घोषणाओं में थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जा रहे हैं। भाजपा इसे चुनावी वादे को पूरा करने का उदाहरण बता रही है। हालांकि, योजना के आवेदन की जटिल प्रक्रिया और कई पात्र महिलाओं को अब तक लाभ नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। 12 से 13 पन्नों के आवेदन पत्र को लेकर भी सवाल उठे हैं। सरकार का कहना है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वास्तविक पात्र लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करना भी नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को राज्य में लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र के साथ समझौते भी किए हैं। हालांकि, आने वाले समय में इन योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने लोगों तक पहुंचता है, यह सरकार के लिए बड़ी कसौटी होगी। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने और अन्य केंद्रीय योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने को भाजपा सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का लाभ इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मिलने का दावा भी सत्ता पक्ष कर रहा है। कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी सरकार के 100 दिनों के एजेंडे में महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई मौकों पर राज्य में कानून का शासन स्थापित होने का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप लगते हैं तो कानून अपना काम करेगा। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों की ओर से कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार के समर्थकों का दावा है कि पिछले 100 दिनों में पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर पहले जैसी व्यापक शिकायतें सामने नहीं आई हैं। निवेश के मोर्चे पर भी सरकार अपने पहले 100 दिनों को उपलब्धियों से भरा बता रही है। कपड़ा उद्योग में बड़े निवेश की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हावड़ा में अमूल के बड़े डेयरी संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इस्पात उद्योग में भी निवेश की परियोजनाएं सामने आई हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर पुरुलिया में इस्पात क्षेत्र से जुड़ी एक और परियोजना का शिलान्यास प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात कही गई है। इन 100 दिनों में सरकार ने कई मोर्चों पर अपने चुनावी एजेंडे को तेजी से लागू करने का प्रयास किया है। सीमा पर जमीन हस्तांतरण से लेकर चिंगड़ीघाटा मेट्रो, बंद चटकलों को खोलने, महिलाओं को आर्थिक सहायता और केंद्रीय योजनाओं के विस्तार तक सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। लेकिन इन कदमों की असली परीक्षा अब शुरू होगी। योजनाएं कितनी स्थायी साबित होती हैं, कितने लोगों तक उनका लाभ पहुंचता है, रोजगार और निवेश के दावे जमीन पर कितना असर डालते हैं और सरकारी घोषणाओं का आम लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सवालों से शुभेंदु सरकार के अगले 100 दिनों और पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन तय होगा।

हिमाचल में 21 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, गिरी जटोन बांध से छोड़ा गया पानी

एजेंसी

शिमला : हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के बीच सिरमौर जिले में स्थित गिरी जटोन बांध का जलस्तर बढ़ने पर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज मंगलवार को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 19, 20 और 21 अगस्त को भी प्रदेश के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी रखा है। 22 से 24 अगस्त के दौरान भी बारिश होने के आसार हैं, हालांकि इन दिनों के लिए किसी प्रकार का चेतावनी अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कुल्लू जिले के कोठी में सबसे अधिक 71 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा धर्मशाला और कसौली में 52-52 मिलीमीटर, काहू में 47 मिलीमीटर, नाहन में 46 मिलीमीटर और चंबा जिले के जोत क्षेत्र में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंगलवार सुबह तक प्रदेश में 105 सड़कें बंद थीं। इनमें मंडी जिले में 39, कुल्लू में 33, सिरमौर में 9, चंबा में 7 तथा शिमला और कांगड़ा में 6-6 सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। शिमला जिले में सबसे अधिक असर चौपाल क्षेत्र में देखा गया है, जहां 22 बिजली ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। ठियोग, रामपुर और चौपाल क्षेत्रों में कुल आठ पेयजल योजनाएं बाधित हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस मॉनसून सीजन में प्रदेश को भारी जनधन हानि उठानी पड़ी है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 30 जून से अब तक बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य आपदाओं से जुड़ी घटनाओं में 196 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 299 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि में 85 घर पूरी तरह नष्ट हुए हैं। इसके अलावा 312 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 14 दुकानें और 270 पशुशालाएं भी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। मॉनसून से अब तक प्रदेश को करीब 994 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। सबसे अधिक 744 करोड़ रुपये की क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है।

मप्र के भिंड में पिकअप-डंपर की भिड़ंत में 8 मजदूरों की मौत, 23 घायल

एजेंसी

भिंड/ग्वालियर : मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सोमवार देररात नेशनल हाइवे-719 पर गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार मजदूरों से भरी पिकअप की सामने से आ रहे डंपर से भिड़ंत हो गई। चंबल रेंज के डीआईजी सुनील कुमार जैन ने इस हादेस में 8 मजदूरों की मौत व 23 मजदूरों के घायल होने की पुष्टि की है घायलों में कई की हालत गंभीर है। सभी घायलों को गोहद स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान और घायलों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया गया है कि हादसा सोमवार देरात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हाइवे पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने वाहन को मोड़ा। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कई मजदूर वाहन में फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में पांच मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया , जबकि तीन मजदूरों की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल, एसडीओपी महेंद्र गौतम, चोराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव, गोहद थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और ऐंडोरी थाना प्रभारी विवेक प्रभात सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सूचना मिलते ही डायल-108 की पांच एंबुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा डायल-112 की मदद से भी घायलों को बाहर निकालकर गोहद अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया है। कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पांच शव गोहद और तीन शव ग्वालियर में रखे गए हैं। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है तथा उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पछगवां और आसपास के गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के पास चिनौर गांव में धान की रोपाई का काम करने आए थे। काम पूरा होने के बाद मजदूर पिकअप वाहन से अपने गांवों के लिए रवाना हुए थे। घायल नंदलाल पुत्र छेन बिहारी बताया कि पिकअप में कुल 29 मजदूर सवार थे। सभी अलग-अलग गांव के थे। गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पिकअप की गति करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होने का अनुमान है। इसी दौरान हाइवे पर बैठे मवेशी अचानक सामने आने से चालक ने उन्हें बचाने की कोशिश की। वाहन अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा से आ रहे डंपर से जा भिड़ा।

सराफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली : घरेलू सराफा बाजार में आज शुरूआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ है। वहीं चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के ज्यादातर सराफा बाजार में सोना आज 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,55,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,42,710 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सराफा बाजार में आज भी 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,55,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,55,720 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,760 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,42,710 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,55,820 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,55,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,42,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजार में भी आज सोना शुरूआती कारोबार के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,42,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

होजाई के नंदपुर गांव में एसएसबी ने चलाया पौधरोपण अभियान, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

गुवाहाटी : पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुवाहाटी के सोनापुर स्थित प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ह्लजीह्न समवाय ने मंगलवार को होजाई के नंदपुर गांव में स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाया। अभियान का आयोजन प्रथम वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में ह्लजीह्न समवाय, होजाई के समवाय प्रभारी इंस्पेक्टर (जीडी) मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में एसएसबी के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान नंदपुर गांव के विभिन्न उपयुक्त स्थानों पर फलदार, छायादार एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों को पौधों के महत्व, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। समवाय प्रभारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं। वे स्वच्छ वायु, छाया और फल प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाना तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समवाय प्रभारी ने स्थानीय नागरिकों से अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने में योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर एसएसबी जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए वृक्षों और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। अभियान के माध्यम से ह्लएक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंह्न का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ एसएसबी और स्थानीय नागरिकों के बीच आपसी सहयोग, समन्वय एवं सामाजिक सहभागिता को भी मजबूत किया। एसएसबी के अनुसार, अभियान का मुख्य उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को प्रकृति और वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें एसएसबी जवानों और स्थानीय नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

जांजगीर-चांपा में 21 वर्षीय युवक का पेड़ से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

जांजगीर : जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खिसोरा में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब खेत की मेड़ पर अर्जुन के पेड़ से 21 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान उदय कुमार कश्यप के रूप में हुई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उदय कुमार कश्यप सोमवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। आज सुबह पिता की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उदय कमरे में मौजूद नहीं था। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और आसपास के इलाकों में खोजबीन की। इसी दौरान खेत की ओर जाने वाले ग्रामीणों की नजर अर्जुन के पेड़ पर फंदे से लटके युवक के शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी गांव के सरपंच को दी। सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान उदय कुमार कश्यप के रूप में की गई। घटना की सूचना नवागढ़ पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मृतक के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है। पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत के पीछे किसी तरह का पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव या अन्य कारण था या नहीं, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है, ताकि उदय की मौत से पहले की परिस्थितियों और उसके संपर्क में रहे लोगों के संबंध में जानकारी सामने आ सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल नवागढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)की नवनियुक्त राष्ट्रीय टीम की पहली परिचय बैठक आगामी 22 अगस्त 2026 को यहां पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएगी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। बैठक में नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव समेत अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। नई टीम के गठन के बाद यह पहला बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी पदाधिकारी एक-दूसरे से औपचारिक रूप से परिचित होंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य नई टीम के बीच आपसी समन्वय और बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके साथ ही पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, जिम्मेदारियों और चुनावी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और संगठन की प्राथमिकताओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने की रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। नितिन नवीन के नेतृत्व में गठित नई राष्ट्रीय टीम में युवा और अनुभवी नेताओं के संतुलन पर जोर दिया गया है। ऐसे में 22 अगस्त की बैठक को नई टीम के बीच कार्य-विभाजन और संगठनात्मक दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के बाद भाजपा की राष्ट्रीय टीम के आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर अधिक सक्रिय भूमिका में दिखाई देने की उम्मीद है।

बीएचयू की प्रो. मधूलिका अग्रवाल विशिष्ट महिला वैज्ञानिक चेयर के लिए चयनित

वाराणसी : उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की प्रो. मधूलिका अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत की विज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नासी-विशिष्ट महिला वैज्ञानिक चेयर के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान प्रो. अग्रवाल को उनके शोध व शिक्षा एवं समान में उसने प्रचार प्रसार के क्षेत्र में किये गये विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह जानकारी मंगलवार को विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क कार्यालय ने दी। जानकारी में बताया गया कि प्रो. मधूलिका अग्रवाल को शोध एवं अकादमिक क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं फेलोशिप भी प्राप्त हो चुके हैं। इनमें फुलब्राइट फेलोशिप, प्रो. पी. शील मेमोरियल अवॉर्ड, प्रो. एच. एल. चक्रवर्ती अवॉर्ड, स्वामी श्रद्धानंद पर्यावरण पुरस्कार (यूजीसी) तथा प्रो. प्रेम दुरेजा एंडोमेंट अवॉर्ड (आईसीएआर) शामिल हैं। इनको देखते हुए नासी-विशिष्ट महिला वैज्ञानिक चेयर के लिए प्रो. मधूलिका अग्रवाल का चयन उनके अकादमिक एवं शोध योगदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है।

सेवई पंचायत भवन में आयोजित एलएल शिविर में 70 अभ्यर्थियों को दिया गया लर्निंग लाइसेंस

मेट्रो रेज संवाददाता

सिमडेगाः उपायुक्त, सिमडेगा कंचन सिंह एवं परिवहन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में नागरिकों को सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 17 अगस्त 2026 को सेवई पंचायत भवन में एलएल शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में कुल 84 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें 15 महिला अभ्यर्थी शामिल थीं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट कराया गया। इसमें सफल 70

अभ्यर्थियों को लर्निंग लाइसेंस निर्गत किया गया, जबकि 14 पुरुष अभ्यर्थी ऑनलाइन टेस्ट में असफल रहे।

शिविर के दौरान अभ्यर्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार वाहन चालक बनने के लिए जागरूक किया गया। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य उपयोग, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन तथा यातायात नियमों के अनुपालन की जानकारी दी गई।

इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने तथा वाहन के आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने के संबंध में भी जागरूक किया गया। अभ्यर्थियों को बताया गया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक जिम्मेदारी है।

बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में हुई भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना

संवाददाता

चक्रधरपुरः बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई । इस अवसर पर भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार और रुद्राक्ष माला से किया गया। श्रृंगार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब हो कि यूं तो प्रतिदिन इस मंदिर में भक्तजनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है किंतु सावन माह में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना और भक्त जनों के बीच व्यापक रूप से प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस संदर्भ में वार्ड पार्षद लीला प्रसाद ने कहा कि सावन माह में भगवान भोले शंकर

के इस मंदिर में सोमवार के दिन उन्हें भव्य रूप से सजाने के साथ-साथ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और भजन कीर्तन के साथ-साथ विशेष पूजा अर्चना भी किए जाते हैं तथा मंदिर परिसर में शिव महिमा के गीत तथा शिव चर्चा भी किए जाते हैं।

मिनी बैजनाथ धाम के नाम से विख्यात महादेव साल में उमड़ी भीड़

चक्रधरपुरः तीसरी सोमवारी पर अनुमंडल के गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत महादेव साल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मिनी बैजनाथ धाम के नाम से विख्यात महादेव साल में अवस्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। यूं तो इस स्थल पर अवस्थित महादेव साल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हमेशा होती है किंतु सावन माह में एक माह तक विशेष पूजा अर्चना के लिए लोग उड़ीसा ,बंगाल, झारखंड व अन्य जगहों से यहां पर आते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल पर लोगों की उपस्थिति देखते ही बनती है। रेलवे के द्वारा भी भक्तजनों की सुविधा के लिए ट्रेनों का ठहराव किया जाता है। सड़क मार्ग से भी लोग इस स्थल पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं महादेव साल में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा व्यापक रूप से भंडारा और प्रसाद का वितरण भी किया जाता है । सड़क मार्ग पर कांवरियों के लिए सेवा भी देखते ही बनती है तथा पूरे सड़क मार्ग पर विभिन्न स्थलों पर लोगों की सुविधा है । साथ ही भंडारा का आयोजन भी किया जाता है । कहा जा सकता है कि श्रधनिष्ठा और रास्ता का अनुपम स्थल महादेव साल में पूरे सावन माह में भक्त जनों के भीड़ देखते ही बनती है।

मुटुर मुसहर हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनी नगरः मोहम्मदगंज थाना अन्तर्गत ग्राम बीरधवर से मृतक मुटुर मुसहर उम्र 60 वर्ष पिता-स्व जानकी मुसहर का अपहरण कर हत्या करने के आरोप में मोहम्मदगंज थाना कांड सं0 31/2026, दि0- 10.08.2026, थारा- 104(1)/61(2)बीएनएस अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, पलामू के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। कांड का अनुसंधान एवं छापामारी के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. दिनेश मुसहर पे लक्ष्मी मुसहर ग्राम रामडीहा थाना नरारी कला खुर्द 2. विकाश मुसहर पिता अवधेश मुसहर ग्राम - बैरिया थाना माली 3. गोविन्द्र मुसहर पे सोहराई मुसहर ग्राम बैरिया थाना माली 4. श्रवण मुसहर पे केतार मुसहर ग्राम रामपुर थाना नविनगर सभी जिला औरंगाबाद (बिहार) को पकड़ कर कड़ाई से पुछ-ताछ के क्रम में मृतक मुटुर मुसहर उम्र 60 वर्ष पे स्व जानकी मुसहर सा बिस्थवर थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू को हत्या करने के नियत से अपहरण कर डेहरी नगर थाना अंतर्गत सोन नदी किनारे पाली रोड शमशान के पास हत्या कर शव को दफनाने की अपना अपराध स्विकार किया। तथा

उनके अपराध स्वीकारोक्ति ब्यान के आधार पर अभियुक्तों के निशानदेही के आधार पर डेहरी नगर थाना अंतर्गत सोन नदी किनारे पाली रोड शमशान घाट के पास से मृतक मुटुर मुसहर के शव (नर-कंकाल) को विधिक कार्रवाई करते हुए कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम हेतू सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया। तत्पश्चात सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दि0- 15.08.2026 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि इस कार्ड के अभियक्त दिनेश मुसहर के पुत्र नन्दन मुसहर का हत्या वर्ष 2025 में दशहरा के समय वादी के पक्ष के द्वारा कर दिया गया था, और शव को कोयल नदी के बहता पानी में फेक दिया गया था। इसलिए बदला के भावना से एक दुसरे का हत्या किया गया। उक्त हत्या में संलिप्त अपराधकर्मी 1. सतोष मुसहर पिता मानदेव मुसहर 2. धरमेन्द्र मुसहर पिता मुटुर मुसहर 3. नन्दु मुसहर पिता स्व० भजन मुसहर सभी ग्राम बीहधवर थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू के विरुद्ध मोहम्मदगंज थाना कांड सं0-33/2026 दि0- 17.068. 2026 धारा- 140(1)/ 61(2) आ/130 (1) बीएनएस दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में नन्दन मुसहर के हत्या में संलिप्त अभियुक्त 1. सतोष मुसहर पिता मानदेव मुसहर 2. धरमेन्द्र मुसहर पिता मुटुर मुसहर सा बिरधवर थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायीक हिरासत में भेजा जा रहा है।

घटनास्थल से बरामद / जब्त

सामान का विवरणीः

-मृतक मुटुर मुसहर का शव (नर कंकाल)

-अनुसंधान / छापामारी में सम्मिलित पदाधिकारी एवं जवान

-भापु से दिव्यांश शुक्ला (अनुपुपदा हुसैनाबाद)

-पुअनि नारायण सोरेन (थाना प्रभारी)

-पीओएन मनोज मुंडा (जांचकर्ता)

-कड़ाही। राजू गुप्ता (देवरी ओपी प्रभारी)

-पुअनि मुकेश कु सिंह (लठेया पिकेट प्रभारी)

- सअनि क्यामुद्दीन अंसारी (मोहम्मदगंज थाना)

एच. शुशील मिंज (सशस्त्र बल)

आ0-671 महेन्द्र भारती (सशस्त्र बल)

80वें स्वतंत्रता दिवस पर

209 कोबरा के उप कमांडेंट और उनके सहकर्मी शौर्य चक्र से सम्मानित

मेट्रो रेज

रांचीः उप कमांडेंट अंजनी कुमार व उनके सहकर्मी दीपक साह ने 21 अप्रैल 2025 को झारखंड के बोकारो स्थित लुगबुरु जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच अदम्य साहस एवं अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए कुल 8 नक्सलियों को मार गिराया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। अंजनी कुमार उप कमांडेंट ने अपनी जान की परवाह किये बिना नक्सलियों की मांद में घुसे और अदभुत पराक्रम का परिचय देते हुए नक्सलियों को मार गिराया। मृत नक्सलियों में बिहार और झारखंड में आतंक का पर्याय बने प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, अरविंद, साहब राम मांझी जैसे बड़े नक्सली लीडर शामिल है। विदित है कि इन नक्सलियों का आतंक पिछले 4 दशक से बिहार और झारखंड के समीपवर्ती इलाके में था।।

इनमें से प्रयाग मांझी सेंट्रल कमिटी सदस्य है जो एक करोड़ का इनामी है।

नक्सली अरबिंद सिंह का आतंक बिहार के जमुई इलाके में भी था ।।

इनके मारे जाने से बोकारो जिला नक्सल फ्री घोषित हो गया है।

यह उपलब्धि झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।।

अंजनी कुमार उप कमांडेंट बिहार के आरा जिले के हाटपोखर गाँव के रहने वाले है। इनके पिता जगदीश चौबे पेशे से मास्टर है । अंजनी कुमार, उपकमांडेंट को उनके अद्भुत शौर्य और बहादुरी के लिए पहले भी दो बार राष्ट्रपति के वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है।

अंजनी कुमार उपकमांडेंट अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जिला से प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए और भारत के प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी क्लियर करके सहायक कमांडेंट के पोस्ट पर 2008 में भर्ती हुए। उसके बाद से ही लगातार देश सेवा में लगे हुए है।

अंजनी कुमार उपकमांडेंट शुरूआती में 6 साल छत्तीसगढ़ के 204 कोबरा बटालियन में रहते हुए बहुत बार नक्सलियों से लोहा लिया और अपना शौर्य का परिचय दिया। उसी दौरान उनकी वीरता के लिए दो बार राष्ट्रपति वीरता मेडल से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देश के सर्वोच्च बल एसपीजी में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अपनी सेवा दे चुके है। इस दौरान भी उन्हें उनकी वीरता के लिए अनेको बार एसपीजी महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है।

देश के सर्वोच्च एलीट फोर्स जंगल वॉरियर के नाम से प्रसिद्ध और नक्सलियों का काल कहे जाने वाले कोबरा में शुरू से ही काम करने की इनकी इच्छा इनको सबसे अलग बनाती है। 6 साल तक झारखंड के खूंटी जिले में 209 कोबरा में अपने कार्यकाल के दौरान अंजनी कुमार उपकमांडेंट का अनेकों बार नक्सलियों से सामना हुआ है।। इस दौरान उनकी अतुलनीय साहस और वीरता के लिए कई बार के रिपु बल के महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वीरता के दो केस अभी प्रक्रियाधीन है।।

सामाजिक उत्थान के लिए *सॉल्यूशन* एक समाधान

जागरूकता, परामर्श व कौशल विकास के विजन से समाज को सशक्त बनाना मिशन : सुबीर कुमार

मेट्रो रेज

पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर): यथा नाम, तथा काम। सॉल्यूशन यानी समाधान। जनहित के कार्यों को धरातल पर उतारने और सरकारी व गैर-सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयासरत स्वयंसेवी संस्था सॉल्यूशन सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित है। यह संस्था वर्ष 2008 से झारखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलीभूत बनाने की दिशा में कार्यरत है। विशेषकर झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के उत्थान और उनकी आजीविका संवर्धन के अवसर सृजित करने के लिए संकल्पित है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देना, कृषि क्षेत्र के विकास व जल संसाधन के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करना, मिट्टी, जल प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जलवायु आधारित कृषि, वाटरशेड मैनेजमेंट, आजीविका संवर्धन व कौशल आधारित शिक्षा के विकास के लिए संस्था विशेषज्ञों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय व सहयोग से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए जागरूकता, परामर्श और कौशल विकास के कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।

सॉल्यूशन झारखंड के सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), सिमडेगा, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि, वॉटर सैनिटेशन सहित अन्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं विकसित करने में समन्वयक की भूमिका निभा रही हैं। संस्था को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारखंड राज्य पंचायती राज, हर घर, जल जीवन मिशन, आईएल एंड एफएस, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सहित विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में

शिक्षा और कौशल विकास पर फोकसः साल्यूशन संस्था का फोकस शिक्षा और समग्र विकास है। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, ड्रॉपआउट रोकना, लड़कियों की शिक्षा,

डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग सिखाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, कृषि कौशल,

वयस्क शिक्षा, निरक्षरों को पढ़ना-लिखना सिखाना,महिला सशक्तिकरण,स्वयं सहायता समूह, बचत-ऋण समूह बनाकर महिलाओं को आर्थिक आजादी, आजीविका परियोजना, घर से काम, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग,

घरेलू हिंसा और बाल विवाह रोकथाम, जागरूकता, हेल्पलाइन, कानूनी मदद,स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, माहवारी स्वच्छता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य,ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त जांच, दवा, टीकाकरण,

कुपोषण उन्मूलन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण कार्यक्रम, काउंसलिंग, नशा मुक्ति अभियान,स्वच्छता और शौचालय, स्वच्छ भारत से जुड़े कार्यों व आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। जैविक खेती, एफपीओ बनाना, बाजार लिंकेज

युवा रोजगार, स्किल इंडिया से जुड़कर ट्रेनिंग और प्लेसमेंटः सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए लोन और मार्केटिंग

वित्तीय साक्षरता, बैंक खाता, बीमा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सामाजिक न्याय और अधिकार,कानूनी साक्षरता, मानवाधिकार, महिला कानून, श्रम कानून दलित, आदिवासी समुदायों के अधिकारों की लड़ाई, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास, कौशल, सहायक उपकरण, बुजुर्ग और अनाथ बच्चों की देखभाल,पर्यावरण और समुदाय विकास,जल संरक्षण तालाब, चेक डैम, वर्षा जल संचयन, सामुदायिक वन और जैव विविधता,आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा में राहत और पुनर्वास, ग्राम विकास, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संस्था द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

सहयोग मिलता है। इस संबंध में सॉल्यूशन के सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि वर्ष 2008 में स्थापित संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित है। समाज के सर्वांगीण विकास के मिशन को लेकर सॉल्यूशन कार्यरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के युवक-युवतियों और आदिवासी समुदाय के आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए संस्था सतत प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि संस्था लगभग 18 वर्षों से झारखंड के विभिन्न जिलों में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है।

संपूर्ण मानव समुदाय के उत्थान के प्रति समर्पित संस्था सॉल्यूशन की कार्यशैली व उपलब्धियों के आधार पर संस्था की साख में वृद्धि हुई है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लिए सॉल्यूशन संस्था की पूरी टीम समर्पित भाव से कार्यरत है।

अब तक जितनी भी परियोजनाओं को लेकर सॉल्यूशन ने कार्य किया है उन परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण सफलीभूत बनाने में संस्था की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उल्लेखनीय है कि विगत लगभग डेढ़ दशक से सॉल्यूशन संस्था ने झारखंड के जिन जिलों में परियोजनाओं को टेकअप किया है, उसे सफलता पूर्वक अंजाम दिया है। संस्था अपने स्तर से विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के दायित्व को भी बखूबी निभाती रही है। सशक्त आधारभूत संरचनाएं विकसित कर सामाजिक सशक्तिकरण को इससे बल मिल रहा है। विशेष कर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वॉटर सैनिटेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सॉल्यूशन सतत प्रयासरत है। समाज के विशेष कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना लक्ष्य है।

हेरिटेज स्कूल के शिक्षक की आत्महत्या

मेट्रोरेज संवाददाता.

मेदिनीनगर, पलामू : सदर थाना क्षेत्र के छेछानी टोला निवासी 28 वर्षीय शिक्षक प्रणव पांडे ने सोमवार रात मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन गंभीर हालत में उन्हें मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। प्रणव चियांकी स्थित हेरिटेज स्कूल में शिक्षक थे। परिजनों के अनुसार वे शांत और स्वभाव से सरल थे। घटना की सूचना पर अस्पताल पुलिस चौकी और सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तथा मामले की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।